

मुक्त संघर्ष

साप्ताहिक

वर्ष: 43 अंक: 27

नई दिल्ली (कुल पेज 16)

2 - 8 जुलाई 2023

मूल्य 7 रुपये

अंदर के पेजों में

समान नागरिक संहिता पर आनन-फानन फैसला प्रतिकूल होगा.....	3
मोदी सरकार की योजनाओं की घोषणाओं और विफलताओं के नौ साल.....	8-9

पटना में विपक्षी पार्टियों की बैठक

भाजपा को 2024 आम चुनावों में हराने का आह्वान



पटना: 18वीं लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता से आरएसएस के एजेंडे पर भाजपा ने त्रुत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने और केंद्र में वाम लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष दलों की सरकार बनाने के उद्देश्य से 23 जून 2023 को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की ऐतिहासिक बैठक संपन्न हुई। बैठक में 15 दलों के 27 प्रतिनिधियों ने शिरकत की और 2024 में लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने पर सहमति बनी। सभी नेताओं ने भाजपा के खिलाफ तत्त्व तेवर दिखलाए और साथ चलने की दुंकार भरी। बैठक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा, माकपा के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी, भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टचार्य, तृणमूल कांग्रेस, राकांपा, शिवसेना, आम

आदमी पार्टी, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन पार्टियों का देश के 11 बड़े राज्यों के रल, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में सरकार है। छह राज्यों बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भाग लिया।

विपक्षी दलों की बैठक में 15 पार्टी के 27 नेता शामिल हुए। जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा, माकपा के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी, भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टचार्य, तृणमूल कांग्रेस, राकांपा, शिवसेना, आम

किरणेश कुमार

नीतीश कुमार, जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जदयू महासचिव संजय झा, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, राजद प्रवक्ता मनोज झा, कांग्रेस के अध्यक्ष मलिकार्जुन खडगे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राकांपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीएमके नेता व तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष व झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिवसेना प्रमुख व महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता व जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पीडीपी की अध्यक्ष व जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, राकांपा की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल, आप नेता राधव चड्ढा और संजय सिंह शामिल हैं।

बैठक में शामिल सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने एक सुर में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए मिलकर संघर्ष का संकल्प लिया।

बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं ने तत्त्व तेवर दिखलाए और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हुंकार भरी। विपक्षी नेताओं ने कहा कि बिहार पहले भी कई बार बदलाव का बिगुल फूंक चुका है। फिर इतिहास दोहराया जाएगा और 2024 में केंद्र की सत्ता से भाजपा हो हटाया जाएगा। भाजपा नेता लालू कृष्ण अडवाणी का रथ भी इसी बिहार में रोका गया था।

बैठक के बाद विपक्षी दलों की संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव महासचिव डी राजा ने कहा कि चुनिंदा कारपोरेट घरानों को फायदा देने के लिए राज्यों की शक्तियां छीनी जा रही हैं। लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए लिए अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराना ही लोकतंत्र को बचाने का एक मात्र रास्ता है। हम सब एकजुट हैं और साथ लड़ेंगे। बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की बदहाली, बेरोजगारी जैसे कई मामले में केंद्र सरकार द्वारा लिए जा रहे फैसले के खिलाफ हमसब मिलकर लड़ेंगे।

भाकपा महासचिव डी राजा ने कहा कि भाजपा शासन के नौ वर्षों में लोकतंत्र, संविधान और मौलिक अधिकारों को समाप्त किया गया है। संवैधानिक संस्थाओं को बर्दाद कर दिया गया है। केंद्र सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर कार्य कर रही है। देश में पूंजीवादी और सांप्रदायिक तात्कालिक एकजुट हो गयी हैं। 2024 की लड़ाई लोकतंत्र, संविधान तथा लोगों को बचाने और नया भारत बनाने के लिए लड़ी जायेगी। केंद्र सरकार संघीय ढांचे को खत्म कर रही है। लोकसभा चुनाव में एकजुट

होकर केंद्र से भाजपा को हटाना होगा। केंद्र सरकार सांप्रदायिक उन्माद पैदा कर रही है और फासीवाद के रास्ते पर बढ़ रही है। केंद्र में बैठी भाजपा सरकार गरीब और मजदूर विरोधी है। इस सरकार में दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़े हैं। देश, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए केंद्र की सत्ता से भाजपा को हटाना होगा।

संवाददाता सम्मेलन में जदयू नेता व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बैठक में शामिल होने वालों को धन्यवाद देते हुए कहा कि भाजपा के खिलाफ लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी पार्टियों ने चुनाव लड़ने पर सहमति जताई है। काफी अच्छी मुलाकात हुई हैं। एक बैठक और होगी, उसमें सारी चीजें अंतिम रूप ले लेगी। सब लोग मिलकर चलेंगे। यह देश के हित में है। जो लोग अभी शासन में हैं, वे देश के हित में कार्य नहीं कर रहे हैं। वे देश के इतिहास बदल रहे हैं। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किये जायेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि आज हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है। राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ ही जनता की आवाज पर भाजपा आक्रमण कर रही है। यह विचारधारा की लड़ाई है। जिसमें हम सभी एक साथ खड़े हैं। हम सभी में थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमने तय किया है एक साथ काम करेंगे। लचीलेपन के साथ अपनी विचारधारा की रक्षा करेंगे। यह विपक्षी एकता की शेष पेज 15 पर...



क्रीब आठ दशक बीत चुके हैं आज, जब जून 22, 1941 को हिटलर ने सोवियत संघ पर फासिस्ट आक्रमण किया था। इस आक्रमण को ‘ऑपरेशन बारबरोसा’ का नाम दिया गया था।

बारबरोसा आक्रमण से छः वर्ष पहले ज्यौर्जी दिमित्रोव, जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के जेनरल सेक्रेटरी थे, और उसकी सातवीं कांग्रेस में उनका भाषण काफी विख्यात हुआ था, जो आज भी है। उसमें, अगस्त 2, 1935 में ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि छठी कांग्रेस के समय से स्पष्ट होता जा रहा था कि फासिज्म का प्रभाव फैल रहा है। उसके आंदोलन का विकसित स्वरूप चारों ओर दिखाई देने लगा था। यह निश्चित है कि फासीवाद वहीं जड़ पकड़ता है जहां उसकी पहुंच होती है। बहुत सारे देशों में फासीवाद का विशाल समर्थन निम्न पूंजीपति वर्ग की जनता में पाया जाता है। बहुत सारे देशों में फासीवाद का कोई प्रभाव जनता में नहीं मिलता और वहां फासीवाद के भीतर भी अंतर्विरोध पाया जाता है। ऐसी स्थिति में फासीवाद में संसद को भंग करने का साहस भी नहीं होता। कुछ समय के लिये यह बुर्जुआ और सामाजिक जनवादी दलों को लोकतंत्र का दिखावा करने की आजादी दे देता है। लेकिन क्रमशः अपने आतंकवादी स्वरूप को प्रकट करने से नहीं चूकता। विरोधी दलों और पार्टियों के खिलाफ खौफ की तानाशाही को जल्द ही लागू कर देता है।

फासीवाद राजसत्ता का कोई स्वरूप नहीं होता, “यह वर्ग, बुर्जुआ और सर्वहारा से परे होता है।” यह निम्न पूंजीपति वर्ग के वित्त पूंजी पर किसी प्रभाव का नाम नहीं है। यह अति दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी हिस्सा है वित्तपूंजी का।

यह वित्तपूंजी के उन साम्राज्यवादी हिस्सों के स्वार्थ में काम करता है जो देश और विश्व के सबसे समृद्ध साम्राज्यवादी होते हैं। लेकिन यह हमेशा अपने आपको तकलीफ में पड़े देशों के साथ सहानुभूति रखने वालों की श्रेणी में ही रखता है। यह जनता को लुभाने के लिये आकर्षक वादे करता है। जर्मनी में यह कहता है, “हमारा कर्तव्य किसी एक व्यक्ति का कल्याण नहीं बल्कि हम पूरे समाज के लिये सोचते हैं।” इटली में यह कहते हैं, “हमारा देश पूंजीपतियों के लिये नहीं है, यह तो सिर्फ कॉरपोरेट्स के लिये है।” जापान के लिये यह चाहता है कि शोषण पूरी तरह निर्मल हो जाय।

ऑपरेशन बारबरोसा

यह समय था साम्राज्यवाद के संकट का, जो विश्व के चरम मुद्रास्फीति का प्रभाव था। उनका एक हिस्सा फासिस्ट आक्रमण की ओर जाने लगा था ताकि मुद्रा स्फीति और जकड़न से मुक्ति मिल सके। 1933 में हिटलर जर्मनी में सत्ता में आ गया। उसके लिये सोवियत संघ एक प्रमुख शत्रु था।

यूरोप के देशों में आर्थिक और सैन्य बल से अधिकार करते हुए उसने कठपुतली सरकार इन देशों में बनाना शुरू किया। इनमें प्रमुख नाम थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, पोलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस और कुछ अन्य देश। संपूर्ण पश्चिमी और पूर्वी यूरोप के हिस्सों में बमबारी चलती रही और देश ध्वस्त होते रहे। द्वितीय विश्व युद्ध सितंबर 1, 1939 में शुरू हुआ और इस समय तक हिटलर ने बहुत सारे देशों में अपना कब्जा जमा लिया था। हिटलर ने

लड़ा गया जहां सबसे अधिक तनाव भरा था टैंकों के युद्ध में। यह खारकोव, मिन्स्क, किएव, दोनबास और लेनिनग्राद के अलावा भी बहुत सारे शहरों और गांवों में चलता रहा। 1944 तक सोवियत सेना रस्सो-यूरोपियन सीमा तक पहुंच चुकी थी और नाजी हिटलर तथा फासिस्ट मुसोलिनी को पूर्वी यूरोप में हरा चुकी थी। अब सोवियत सेना प्रवेश कर रही थी जर्मनी की सीमाओं में। हिटलर ने आत्महत्या कर ली अप्रैल 30, 1945 में और जर्मन सेना ने आत्मसमर्पण सोवियत सेना के समक्ष किया आठ मई, 1945 में। नौ मई को, एक दिन के बाद, जर्मन सेना ने मित्र राष्ट्रों की सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया।

इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ जिसमें पांच करोड़ लोग मारे गए जिनमें दो करोड़ सोवियत जनता और सिपाही थे। क्रीब आधी शताब्दी के बाद भारत अज क्रमशः फासीवाद की जकड़न से घिर रहा है जिसमें वित्तपूंजी की प्रमुख भूमिका है। लगता है लोकतांत्रिक पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। जनता में वित्तपूंजी जो भ्रम फैलाती रही है, उसमें भयानक यथार्थ को छुपा नहीं पा रहा है।

“वॉचडॉग एक्सेस नॉव” के अनुसार, भारत नेटवर्क की तालाबंदी में आज सबसे आगे है। भारत आज टेलिकॉम और सोशल मीडिया को बाध्य कर रहा है कि वह सत्ता के निर्देशनानुसार ही लिखे और अमान्य करने पर पुलिसी कार्रवाई की भी धमकी दे रहे हैं।

भारत की जनता में चौदह प्रतिशत मुसलमान है, पर लंबे समय से उन्हें यातनाओं में रहना पड़ रहा है। भारत की बहुलता में एकता विनष्ट होने की कगार पर आ गई है। ‘ह्यूमन राईट वॉच’ की रिपोर्ट-जो 2019 में आई, उसके अनुसार, हमारे देश में उस दौरान 44 हत्याएं हुई, जिनमें छत्तीस मुस्लिम थे। इन सबको प्राणांतक यातना देकर मारा गया था। उन पर सिर्फ संदेह था, उसकी पुष्टि नहीं हुई थी कि उनके पास गोमांस था, गाएं थीं जिनका वे व्यापार करते थे। इस विचंडन की राजनीति में हिन्दू बहुलवाद को अल्पमत के खिलाफ हवा दी गई।

वित्तपूंजी को ये सारे तत्व चाहिये जिनमें प्रमुख हैं कल्याणकारी समाज के धंस के ढेर और उन्हें स्वेच्छा से या मज़बूर होकर स्वीकृति देने वाली जनता।

प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान

अमेरिका—भारत समझौतों पर हस्ताक्षर

नई दिल्ली: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अमेरिका—भारत समझौते पर निम्नलिखित बयान जारी किया:

अमेरिका की अपनी हालिया राजकीय यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारत—अमेरिका संबंधों को मजबूत करने के लिए 22 जून, 2023 को व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी पर संयुक्त घोषणा जारी की।

अमेरिका के साथ तीन महत्वपूर्ण रक्षा समझौतों की निरंतरता में, 2016 में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एलएमओए), 2018 में संचार संगतता और सुरक्षा समझौता (सीओएमसीएसए), और 2020 में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (बीईसीए), के बीच हालिया समझौते दोनों देश संयुक्त राज्य अमेरिका के रणनीतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए ही इस रक्षा सहयोग को और बढ़ाएंगे।

हालाँकि भारत में हथियारों के सह—उत्पादन के बारे में कई सौदे हैं जो हमारी सैन्य क्षमताओं

को मजबूत कर सकते हैं लेकिन ये समझौते हमारे नौसैनिक अड्डों और सैन्य हवाई अड्डों का उपयोग करके अमेरिकी नौसेना और वायु सेना की आगे की तैनाती के लिए रसद, रखरखाव और मरम्मत के निर्माण की अनुमति देते हैं, यह निश्चित रूप से हमारी रणनीतिक स्वायत्ता से समझौता है। यह अन्य बड़ी शक्तियों को हिंद महासागर के तटीय और भीतरी इलाकों में भी ऐसा करने के लिए उकसाएगा, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में हथियारों की होड़ बढ़ जाएगी।

संयुक्त बयान में यूक्रेन में युद्ध से लेकर म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली तक सभी मुद्दों पर चर्चा की गई है, लेकिन फिलिस्तीनी लोगों पर इजरायल द्वारा रोजाना किए जा रहे हमलों पर चुप्पी साध ली गई है। दुर्भाग्य से, यहां जिओनवादी इजराइल के समर्थक और हिंदुत्व के कट्टरपंथी कबीले एक साथ आते हैं। भाकपा भारत सरकार से उस अमेरिकी साम्राज्यवादी शक्ति का पिछलगू बने बिना स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का आव्वान करती है, जो चाहता है कि एशिया—प्रशांत क्षेत्र में उनकी आधिपत्यवादी नीति को लागू करने के लिए भारत सबसे अच्छा विकल्प हो।

किसान नेता कामरेड तेज सिंह वर्मा नहीं रहे

आगरा: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और किसान सभा के विष्ट नेता कामरेड तेज सिंह वर्मा जी का 15 जून 2023 को सुबह साढ़े छह बजे उनके मलपुरा स्थित निवास पर अचानक निधन हो गया। कामरेड वर्मा 84 वर्ष के थे, तथा गत दो महीने से प्रोस्टेट बीमारी से पीड़ित थे, जिसका आपरेशन 12 जून को हुआ था।

8 जूनवी 1940 को किसान परिवार में जन्मे कामरेड वर्मा मैट्रिक पास करने के बाद भारतीय जीवन बीमा निगम की सेवा में चले गये किन्तु अपने पिताजी के कहने पर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और खेतीबाड़ी में लग गए। कामरेड वर्मा वर्ष 1980 में पार्टी में शामिल हो गये और किसान सभा के मौर्चे कार्य करने लगे आगरा की सदर, खेरागढ़, किरावली तहसीलों में गांव—गांव किसान सभा की इकाइयों के गठन में उनकी आहम भूमिका रही।

किसानों के सिंचाई, नहरों की सफाई, फर्जी आवपआसई, फर्जी ताबान, भूमिहोनों को पट्टे दिलाने, पुलिस उत्तरांड़न आदि के खिलाफ चले संघर्षों में उनकी प्रमुख भूमिका रही। वर्ष 1989 में मलपुरा में पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस द्वारा अकारण किये गये लाठीचार्ज में दो कार्यकर्ताओं के घायल

होने के फलस्वरूप पुलिस के खिलाफ चले लम्बे आंदोलन में उनकी भागीदारी रही जिसमें 14 अन्य कार्यकर्ताओं के साथ उनके ऊपर भी पुलिस ने कई मुकदमे लगाये।

कामरेड वर्मा जी ने वर्ष 1993 में एक किसान आंदोलन में 10 दिन की जेल यात्रा भी की। कामरेड वर्मा अकोला ब्लाक उप प्रमुख एवं क्षेत्रीय सहकारी समिति के अध्यक्ष के पद पर भी रहे।

समान नागरिक संहिता पर आनन-फानन फैसला प्रतिकूल होगा

समान नागरिक संहिता की वकालत में प्रधानमंत्री की हालिया घोषणा का उलट असर होगा चूंकि आरएसएस-भाजपा एक ऐसे नारे की तलाश में है जो कि इन्हें 2024 के चुनाव से पूर्व अच्छा फायदा दिला सके। जैसा कि वर्तमान सरकार उस जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में सभी मोर्चे पर असफल रही है जिसने उन्हें एक छत्र राज के लिए भारी बहुमत से विजयी बनाया।

हाल ही में कर्नाटक चुनावों में शर्मनाक हार के बाद, भाजपा-आरएसएस मध्यम वर्ग का ध्यान भटकाने के लिए विशेष रूप से 5 राज्यों में आगामी चुनावों के मददेनजर और विशेष रूप से संसदीय चुनावों के लिए एक साधन या नारे की खोज कर रही है। इसलिए 22वें विधि आयोग का हाल का संविधान एक और धृषित प्रयास है, वहीं वे अपने झूठ के विश्वविद्यालय से एक पक्षीय राय पेश गढ़ते हुए अपने अनुकूल फैसले को पाने की कोशिश में हैं।

वास्तव में, 22वें आयोग के विषय में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछली आयोग की रिपोर्ट 2018 में नागरीय समाज से भारी प्रतिक्रिया मिलने के बाद प्रस्तुत की गई थी। 2018 की आयोग की रिपोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस स्तर पर समान नागरिक संहिता का गठन न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है। इसने आगे कहा कि नागरिक संहिताओं में विभिन्नताओं की उपस्थिति का होना जरूरी नहीं है कि वे भेदभावपूर्ण व्यवहार का संकेत हैं, बल्कि यह एक मजबूत और जीवंत लोकतांत्रिक प्रणाली का संकेत है।

आयोग ने आगे कहा कि सांस्कृतिक

विविधता वाली आबादी के बीच एक रूपता को बढ़ावा देने वाले कानूनी ढंगे पर भरोसा करने के बजाय कई देश मतभेदों को स्वीकार करने और उन्हें समायोजित करने की दिशा में अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। समान प्रावधान वंचित और कमजोर समूहों के प्रति अन्यायपूर्ण होते हैं। विविधता के उत्तर से किसी विशेष समूह के लिए नुकसान नहीं होता है। समानता के

सैयद अजीज पाशा

को जल्दबाजी में इस तरह लागू नहीं करेगा, कि मुसलमान, ईसाई समेत विभिन्न धार्मिक समुदाय या कोई अन्य समुदाय द्वारा इसे आपत्तिजनक माना जा सकता है। मेरी राय में, सरकारों द्वारा इस तरह की नीति का कार्यान्वयन अत्यधिक तर्कहीन होगा।

जनगणना के अनुसार हमारे पास 19,500 मातृभाषाएं हैं। सांस्कृतिक विरासत समृद्ध और विविधतापूर्ण है। अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों में, संपत्ति समुदाय के स्वामित्व में है, लेकिन व्यक्तियों के स्वामित्व में नहीं। यहाँ तक कि भारत में पितृसत्ता समाज का दबदबा है, लेकिन आपको पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ स्थानों में मातृसत्तात्मक समाज मिल सकता है।

जनजातीय/आदिवासी समदायों के बीच विवाह और मृत्यु की विभिन्न रसमें हैं। 2016 में, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने अपने बहुविवाह अधिकारों, विवाह और मृत्यु अनुष्ठानों के संरक्षण के लिए, जो हिंदू धर्म से अलग हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत की। समान नागरिक संहिता पर जोर देने के प्रमुख उद्देश्य का आशय मुस्लिम समुदाय के प्रति एक झूठी धारणा पेश करना है की वे चार पत्नियों को रख सकते हैं। नवीनतम जनगणना में कहा गया है कि 1,000 पुरुषों की आबादी पर केवल 922 महिलाएं हैं। तो एक से अधिक शादी करने का सवाल कहाँ है? यदि आप विभिन्न धार्मिक समुदायों में बहुविवाह के बारे में गणना करते हैं तो "हम चार, हमारे चालिस" का दुष्प्रचार करने वाला नारा एक एक दुष्टता है। 1961 की जनगणना बहुविवाह को रिकॉर्ड करने वाली अंतिम जनगणना है जिसमें कहा गया है कि कुल आदिवासीयों की आबादी के 15.25 प्रतिशत में, कुल बौद्ध आबादी के 7.9 प्रतिशत में, कुल जैन आबादी के 6.72 प्रतिशत में, कुल हिंदू आबादी के 5.80 प्रतिशत में और कुल मुस्लिम आबादी के 5.70 प्रतिशत में बहुविवाह व्याप्त है।

इसलिए 21 से लेकर 22वें विधि आयोग तक की पांच वर्षों की छोटी अवधि ने इस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं बनाया है। डा. बी. आर. अंबेडकर ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि राज्य अपने अधिकार



अधिकार से समझौता किए बिना महिलाओं को अपने विश्वास का पालन करने की स्वतंत्रता की गारंटी 21वें विधि आयोग ने समुदायों के अंतर्गत लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने की दिशा में एक मजबूत झुकाव दिखाया है।

इसलिए 21 से लेकर 22वें विधि आयोग तक की पांच वर्षों की छोटी अवधि ने इस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं बनाया है। डा. बी. आर. अंबेडकर ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि राज्य अपने अधिकार

विधि विशेषज्ञों का तर्क है कि यदि पहले से ही संहिताबद्ध दीवानी और आपराधिक कानून में बहुलता है, तो विभिन्न समुदायों के विविध व्यक्तिगत कानूनों पर एक राष्ट्र, एक कानून की अवधारणा कैसे लागू की जा सकती है। किसी भी समाज ने, जिसने सजातीय बनने की कोशिश की है, अंततः ठहराव और गिरावट का अनुभव किया है। एक एकीकृत राष्ट्र को अनिवार्य रूप से एक रूपता की आवश्यकता नहीं थी और कहा कि धर्मनिरपेक्षता देश में बहुलता का खंडन नहीं कर सकती। हमारे देश में विविधता अद्वितीय है और

इसलिए इस शरारती नारे का

से रोका गया और कर्मचारियों को अचानक बेरोजगारी से भी बचाया गया। इससे व्यापार के अलावा, स्कूल भवनों, सड़कों, पानी, बिजली आपूर्ति आदि जैसे विकासात्मक उद्देश्यों के लिए भी धन उपलब्ध हो गया, लेकिन 1992 से निजीकरण और उदारीकरण की नीति के आगमन के साथ, योजना को छोड़ दिया गया, जिससे कमी आई। ग्रामीण विकास में बैंकों की भूमिका। बैंकों के संचालन में व्यापार और उद्योग को फिर से प्राथमिकता मिली। यहाँ भी, चूंकि बड़े ऋण अधिक लाभदायक थे, इसलिए छोटे उद्योग की उपेक्षा की गई। बैंकों का पैसा लगभग विशेष रूप से बड़े कारपोरेट्स के पास जाने लगा, 1992 के उदारीकरण के साथ, ब्याज दरें कम हो गई, कारपोरेट्स को ऋण

जनता के पैसे की बैंकों के माध्यम से लूट

डॉ. श्रीनिवास खाण्डेवाले

संस्थानों और नागरिकों के प्रति सरकार की समग्र जिम्मेदारी।

सरकार की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि इन सभी मुद्दों से कैसे निपटा जाता है। सरकार की इसी विश्वसनीयता के आधार पर मतदाता विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का चुनाव करते हैं। इसलिए, हालांकि ये मुद्दे अलग-अलग मुद्दों के रूप में दिखाई देते हैं, वे ऊपर उल्लिखित शृंखला का एक हिस्सा हैं।

अभी तक क्या हुआ है?

आजादी से पहले, और उसके बाद

2019 में आरबीआई ने स्पष्ट रूख अपनाया कि विलफुल डिफॉल्टर्स के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यह स्थिति किसके आदेश पर बदली गयी है?

आरबीआई ने 8 जून, 2023 को एक अधिसूचना जारी की। इसने वाणिज्यिक बैंकों को विलफुल डिफॉल्टर्स (जो बैंकों से ऋण लेते हैं, लेकिन ऐसा करने की क्षमता होने के बावजूद उन्हें चुकाते नहीं हैं) के साथ समझौता करने और बकाया ऋण एक बार और हमेशा के लिए उनका निपटान करने की अनुमति देता है। अधिसूचना में आगे कहा गया है, ऐसे डिफॉल्टर्स के खिलाफ शुरू की गई कोई भी आपराधिक प्रक्रिया जारी रहेगी, संबंधित बैंक को यह सावधानी बरतनी थी कि इस तरह के बयान पर बातचीत करते

शेष पेज 6 पर...

बिहार में जेल भरो आंदोलन को मिली शानदार सफलता

पटना: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत बिहार के सभी जिला समाहरणालय पर जन सत्यग्रह और जेल भरो आंदोलन संपन्न हो गया। इस आंदोलन को अपार सफलता मिली। बहुत दिनों के बाद इस तरह के आंदोलन आयोजित किये गए। जिसमें करीब डेढ़ लाख लोगों की जनभागीदारी हुई। 20 जून को राज्य के सात जिलों मधुबनी, बेगूसराय, दरभंगा, सहरसा, बांका, नवादा और शिवहर में भाजपा हटाओ देश बचाओ और नया भारत बनाओ नारे के साथ जन सत्यग्रह और जेल भरो आंदोलन आयोजित किये गए जबकि गया में 21 जून को कार्यक्रम आयोजित किये गए। इससे पहले आठ और नौ जून को बिहार के 29 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किये गए थे।

कोरोना काल के बाद इस तरह की पहली कार्रवाई आयोजित की गई। इस आंदोलन से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ता में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आंदोलन की तैयारी को लेकर गांव गांव पदयात्रा निकाली गई। हजारों नुकड़ सभा आयोजित की गई। मोटर साईकिल रैली निकाली गई। यह आंदोलन केंद्र की जन विरोधी भाजपा सरकार को हटाने के लिए आयोजित की गई।

भाजपा हटाओ, देश बचाओ, नया भारत बनाओ, नारे के साथ जन सत्यग्रह और जेल भरो आंदोलन चलाया गया है। सुबह साढ़े नौ बजे से समाहरणालय का गेट जाम कर दिया गया। दरभंगा में जिलाधिकारी कार्यालय का गेट तोड़कर आंदोलनकारी अंदर प्रवेश कर गए। बेगूसराय में आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर सदर थाने ले जाया गया। थाने में आंदोलनकारियों को रखने के लिए जगह नहीं थी। सहरसा में भी पुलिस आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर थाने

ले गई। थाने में जगह नहीं थी। इसलिए आंदोलनकारियों को तुरंत रिहा कर दिया गया।

मधुबनी में आंदोलन का नेतृत्व राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय, जिला सचिव मिथिलेश कुमार झा, संजय चौधरी, राजश्री किरण, बेगूसराय में जिला सचिव अवधेश कुमार राय, राज्य सचिवमंडल सदस्य राजेन्द्र प्रसाद सिंह, विधायक रामरतन सिंह, विधायक सूर्यकांत पासवान, दरभंगा में राष्ट्रीय सचिव व पूर्व सांसद नारेंद्र नाथ ओझा, जिला सचिव नारायण जी झा, सहरसा में राज्य सचिव मंडलसदस्य ओमप्रकाश नारायण, जिला सचिव परमानन्द ठाकुर, पूर्व जिला सचिव विजय कुमार यादव, बांका में राज्य सचिव मंडल सदस्य व पूर्व विधान पार्षद संजय कुमार, नवादा में प्रो. जयनंदन सिंह और शिवहर में राज्य सचिवमंडल सदस्य रामचंद्र महतो, राज्य सचिव मंडल सदस्य अजय कुमार सिंह, जिला सचिव सत्रुघ्नि



सरकार पर जमकर हमला बोला। मोदी सरकार सभी मोर्चे पर फिसड़ी साबित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को फासीवादी रास्ते पर ले जाना चाहती है। देश में साम्प्रदायिक जहर घोला जा

बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं, हमदर्द और राज्य की जनता को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि बिहार के 38 में से 37 जिलों में आंदोलन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया



सहनी, गया में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जानकी पासवान, राज्य कार्यकारिणी सदस्य अखिलेश कुमार जिला सचिव सीताराम शर्मा, मसूद मंजर आदि ने आंदोलन का नेतृत्व किया और गिरफ्तारी दी।

आंदोलन के दौरान वक्ताओं ने केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी

रहा है। साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। महंगाई आसमान छू रही है। इस सरकार में दलित, आदिवासी, महिलाओं और अल्पसंख्यक पर अत्याचार बढ़े हैं। बेरोजगारी बढ़ी है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। कल कारखाने बंद हो रहे हैं।

भाकपा राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने इस आंदोलन को सफल

है जबकि सुपौल में 27 जून को कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि

यह आंदोलन संविधान की रक्षा करने, महंगाई पर रोक लगाने, किसानों को समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी करने, बेरोजगारों को रोजगार देने, जिके कंपनीकरण की साजिश पर रोक लगाने, मनरेगा के बजट में की गई कटौती वापस लेने, अडानी-अम्बानी पक्ष में बनाई जा रही नीति पर रोक लगाने, सार्वजनिक उपक्रमों के सौदे को रद्द करने, मौलिक अधिकारों पर हमले बंद करने, केन्द्रीय जाँच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को रद्द करने, समान शिक्षा की नीति लागू करने आदि मांगों को लेकर आयोजित किये गए। मोदी सरकार में लगातार संवैधानिक अधिकारों पर हमले किये जा रहे हैं। मोदी सरकार भाजपा आरएसएस के एजेंडे को देश पर थोपना चाहती है। इस सरकार में महंगाई आसमान छू रही है।

बिजली की कीमत में की गई बढ़ोत्तरी वापस ले केन्द्र सरकार



पटना, 25 जून, 2023: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पाण्डेय ने पहले से महंगी बिजली की मार झेल रहे उपभोक्ताओं पर केन्द्र सरकार द्वारा रात्रि में बिजली खपत करने पर बिजली की कीमत में की गई बढ़ोत्तरी की तीखे शब्दों में निन्दा की और केन्द्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है। भाकपा के राज्य सचिव राम नरेश पाण्डेय ने बयान जारी कर कहा कि केन्द्र सरकार के बिजली मंत्रालय ने रात्रि में उपभोक्ताओं द्वारा बिजली के खपत पर 20 प्रतिशत बढ़ोत्तरी करने का निर्णय लिया है जो जनविरोधी है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय का असर देश के शहरी और ग्रामीण इलाकों के बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। रात्रि में बिजली का उपयोग केवल एसी और कुलर में रहने वाले उपभोक्ता ही नहीं करते बल्कि मध्यम और सामान्य लोगों के अलावे गरीब, मजदूर किसान और छोटे-छोटे उद्योग चलाने वाले लोग भी करते हैं। इस बढ़ोत्तरी का असर वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा।

राज्य सचिव राम नरेश पाण्डेय ने केन्द्र सरकार से इस फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की है। उन्होंने इस बढ़ोत्तरी के खिलाफ पार्टी के तमाम इकाईयों एवं आम-अवाम से कड़ा विरोध जताने का आव्हान किया।

गारंटीशुदा न्यूनतम समर्थन मूल्य से राहत

जून के शुरुआती दिनों में भारतीय कृषि क्षेत्र में तीन महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं। किसानों ने कुरुक्षेत्र में सरकार ने घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सूरजमुखी के बीज खरीदने से इनकार कर दिया। दूसरी घटना, केंद्र सरकार ने मौजूदा खरीफ सीजन के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा की और तीसरी घटना है सरकार की किसानों को प्रधानमंत्री किसान फंड की वर्तमान किस्त की घोषणा।

किसानों का आंदोलन कपूरथला में तब शुरू हुआ जब हरियाणा सरकार ने 6,400 रुपये प्रति विवंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार किसानों से सूरजमुखी के बीज खरीदने से इनकार कर दिया, जबकि प्रति विवंटल बाजार मूल्य 4,000 रुपये से 4,800 रुपये तक पहुंच गया। कपूरथला, अंबाला और पंजाब के पड़ोसी जिलों से 2,000 सूरजमुखी किसानों ने चंडीगढ़ राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया और राज्य सरकार से मांग की कि वह कीमत नुकसान की भरपाई करे और फसल की खरीद के लिए पांच लाख रुपये का भुगतान करे। हालांकि, संयुक्त किसान निकाय एसकेएमयू के नेतृत्व में लगभग दो सप्ताह के आंदोलन के बाद, राज्य सरकार ने भावांतर योजना के तहत किसानों के घाटे की भरपाई करने पर सहमति व्यक्त की है।

भारत में वनस्पति तेलों की भारी कमी है। हरियाणा में सरसों की फसल पर किसानों को इस सीजन में अकेले 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। चावल और गेहूं की खेती की एकल कृषि, भूजल का अत्यधिक उपयोग और पराली जलाने को सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जाना चाहिए। किसानों को इन फसलों के स्थान पर तेल, बाजरा और दालों की खेती करनी चाहिए। केवल सूरजमुखी ही नहीं, बल्कि सरसों, सोयाबीन, लाल चना और आम जैसी अन्य फसलों की कीमत में मंदी है जिससे किसानों को उत्पादन पर अधिक लागत की तुलना में उत्पाद कम कीमत पर बेचना पड़ता है।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कार्यरत केंद्रीय कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसपी) द्वारा उत्पादन की लागत को कम करके आंका जा रहा है, उत्पादन की लागत का अवमूल्यांकन ने किसानों को संकट में धकेल दिया है, जबकि बाजार में अन्य सभी खिलाड़ियों-बिचौलियों, थोक और नियर्यात व्यापारियों और सुपरमार्केट कॉर्पोरेट एग्रीबिजनेस वैल्यू चेन ने शानदार मुनाफा कमाया है। यह भी

संदेह है कि बाजार में घोषित कीमतों को जानबूझकर कम रखा गया है ताकि किसान की कीमत पर बाजार में अन्य सभी खिलाड़ियों को लाभ पहुंचाया जा सके।

कम एमएसपी से किसानों को भारी नुकसान

वर्तमान खरीफ सीजन के लिए विभिन्न फसलों के लिए एमएसपी की हाल की घोषणाएं बहुत कम हैं। चावल, गेहूं, ज्वार और कपास में घोषित एमएसपी में 4 से 8 प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई है। वर्ष 2014-22 की अवधि के दौरान लाभकारी फसल खरीद मूल्यों और किसानों की आय दोगुनी करने के वर्तमान सरकार के जोरदार बादों के बावजूद विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की औसत वार्षिक वृद्धि 4 से 8.1 प्रतिशत के बीच रही। जबकि पूर्व यूपीए शासन (2004 से 2013 के बीच) के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि 7.2 से 11.3 प्रतिशत के बीच थी। बढ़े मूल्य के साथ 2023 में खरीफ के लिए 2183 रुपये प्रति विवंटल (पिछले सीजन के 2040 रुपये की तुलना में 7.4 प्रतिशत वृद्धि) और गेहूं 2,260 रुपये प्रति विवंटल की घोषणा की गई है।

सरकारी खरीद (अधिकतर पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ से) धान और गेहूं तक सीमित है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से स्लैब में वृद्धि सुनिश्चित होती है और खुले बाजारों में अपेक्षाकृत अधिक मूल्य प्राप्त होते हैं। बड़ी संख्या में छोटे, काशतकार किसान अपनी उपज को सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से बहुत कम दरों पर मिलों और बिचौलियों को बेच देते हैं, क्योंकि वे दूर स्थित अनाजमंडी तक अपने अनाज पहुंचाने के लिए परिवहन खर्च बहन नहीं सकते हैं।

हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि इसकी घोषित कीमतें कृषि की सभी लागतों को कवर करती हैं, लेकिन एफ2 फॉर्मूला (फसल जुताई लागत और परिवारिक श्रम का जोड़) किसानों द्वारा किए गए अन्य सभी खर्चों को आसानी से अनदेखा करता है। एमएस स्वामीनाथन आयोग ने सी2+50 प्रतिशत फार्मूले की सिफारिश की थी, जिसमें समग्र जुताई लागत के कुल मूल्य के साथ अतिरिक्त 50 प्रतिशत जोड़ गया है।

सरकार द्वारा घोषित एमएसपी की

डा. सोमा मार्ला

गणना में दो तरह की गलतियाँ हैं।

पहली गलती, सीएसपी (केंद्रीय कृषि लागत और मूल्य आयोग) मूल्यों की गणना के लिए आधार के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 को लेता है न कि पिछले सीजन के मूल्य को। पिछले 10 वर्षों के दौरान उर्वरकों (विशेष रूप से डीएपी और पोटाश), डीजल, कीटनाशकों, परिवहन और भूमि तैयार करने की लागत में द्वाई गुना वृद्धि हुई है। लेकिन आयोग अभी भी पुरानी कीमतों पर चिपका हुआ है और इस प्रकार बनावटी ढंग से खेती की लागत कम कर रहा है।

कृषि मूल्य लागत गणना के 'एफएल' फार्मूले और स्वामीनाथन के 'सी2+50' प्रतिशत में अंतर

इस महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 14 फसलों के लिए घोषित खरीफ एमएसपी में चावल, गेहूं और अन्य फसलों के लिए औसत वृद्धि लगभग 7.4 प्रतिशत है। केवल तिल और हरे चने में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस साल सीएसपी ने फॉर्मूला एफएल (फसल जुताई खर्च और परिवारिक श्रम) का उपयोग करके एमएसपी की गणना की और सिफारिश की है। लेकिन डा.स्वामीनाथन आयोग ने सुझाव दिया कि सी2.50 प्रतिशत फॉर्मूले (सी2.5, खेती की कुल या व्यापक लागत) में सभी फसल की खेती का खर्च, जमीन किराया, ट्रैक्टर और अन्य निवेशों की पूंजीगत लागत पर व्याज शामिल हैं। जबकि सीएसपी ने सुझाव दिया कि पिछले सीजन के दौरान उर्वरकों, डीजल और अन्य की तात्कालिक कीमतों के आधार पर 'ए' की गणना

की गई थी, लेकिन गणना का आधार वर्ष 2012-13 की कीमतों में बना रहता है। इन दस सालों की अवधि के दौरान मूल्य लगभग 2.5 गुना बढ़े हैं। यही नहीं, पूरा परिवार (औसतन 4 सदस्य का) फसल जुताई के दौरान मेहनत और फसल कटाई आदि काम करता है, और फसल उत्पादन के दौरान दो सदस्यों की मेहनत को गणना में शामिल करने पर विचार करना चाहिए।

एफएल और सी2+50 प्रतिशत के बीच के अंतर से निर्धारित मूल्य में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। (वर्ष 2022 के लागत कीमत) के हिसाब से चावल के लिए प्रति विवंटल एमएसपी सरकार द्वारा घोषित 2,183 रुपये के बजाय 3,340 रुपये होना चाहिए। जहाँ सुबोध वर्मा और पीयुष शर्मा ने अपने लेख में 2012 की लागत कीमतों का इस्तेमाल किया, जो सी2+50 प्रतिशत फार्मूला के हिसाब से चावल का प्रति विवंटल मूल्य लगभग 2,700 रुपये होना चाहिए। इस प्रकार, पिछले 5 वर्षों के दौरान, सीएसपी (केंद्रीय कृषि लागत और मूल्य आयोग) द्वारा चावल के लिए की गई दोषपूर्ण गणना के कारण किसानों को 2.40 लाख करोड़ रुपये का उपयोग करके एमएसपी की गणना की और सिफारिश की है। लेकिन डा.स्वामीनाथन आयोग ने सुझाव दिया कि कारण किसानों को 2.40 लाख करोड़ रुपये के लिए लगभग 5.85 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

उपरोक्त वर्णित नुकसान को छिपाने के लिए, वर्तमान और पिछली सरकारें नियमित रूप से किसानों को समय-समय पर नाममात्र के, लुबावने प्रोत्साहन बाँटती है। उदाहरण के लिए, हाल ही में प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये की जारी की गई किस्त, एक और जुमला है। यह खेरात और कम न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रत्येक फसल मौसम में किसानों द्वारा किए गए भरपाई करते हैं। प्रधानमंत्री किसान का पैसा देकर सरकार ने उर्वरकों, सिंचाई, बिजली, फसल बीमा, प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान आदि से सब्सिडी पूरी तरह से वापस ले ली है।

घोषित एमएसपी की कानूनी गारंटी से किसानों का बचाव

अखिल भारतीय किसान सभा, एसकेएमयू और अन्य किसान संगठन कुछ हद तक किसानों को राहत दिलाने के लिए एमएसपी घोषित मूल्यों की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। चूंकि आबादी का 70 प्रतिशत गांवों में रहता है ऐसे में 50 खरब (5 ट्रिल्यन) डॉलर की अर्थव्यवस्था केवल बढ़ती ग्रामीण आय और मांग के फैलाव से हो सकती है।

25 दिनों के अंदर दूसरी वार टकराई ट्रेन, चिंता का विषय

पटना, 26 जून 2023: भारतीय कम्प्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने पश्चिम बंगाल बांकुड़ा जिले में हुई ट्रेन दुर्घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल दुर्घटना के 25 दिनों के अंदर उसी तरह दूसरी बार 25 जून को पश्चिम बंगाल में दो मालगाड़ी ट्रेन टकरा गई है।

यह बहुत ही गंभीर मामला है। गंभीर चिंता व्यक्त की है। जबकि ट्रेन दुर्घटना होती रहती है। मोदी सरकार रेलवे को भद्रता बैठ गया है। मोदी सरकार ने रेल का बजट भी समाप्त कर दिया है। इस कारण भी रेलवे के बच रखा है। भाकपा राज्य सचिव ने केंद्र सरकार से रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है।

संयुक्त किसान मोर्चा का बिहार में किसान महापंचायत का ऐलान

पटना, 27 जून 2023: किसानों के मसीहा स्वामी सहजानंद सरस्वती की 73वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित विशाल किसान कन्वेशन में संयुक्त किसान मोर्चा, बिहार द्वारा राष्ट्रकवि दिनकर की 100वीं जयंती के शुभ अवसर पर जो धरती को जोते बोए वो धरती का मालिक होवे के आव्वान के साथ 23 सितंबर को 2023 को बिहार में किसानों की विशाल महापंचायत लगाने का जंगी ऐलान किया।

24 सितंबर 2023 को बिहार से किसानों का विशाल कारवां विधानसभा को धेरने पटना पैदल कूच करेगा। दिनेश सिंह, अशोक प्रसाद सिंह, अनिल कुमार सिंह, रामायण सिंह, आशीष रंजन, मनोज कुमार और बाल गोविंद सिंह की सात सदस्यीय अध्यक्षमंडली ने इस कन्वेशन की



अध्यक्षता की। सर्वप्रथम दिनेश सिंह ने दिल्ली किसान आंदोलन में शहीद हुए 750 किसानों, लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसान एवं पत्रकार, मणिपुर हिसा में और बालासोर की ट्रेन दुर्घटना में मारे गये सभी लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों ने 2 मिनट खड़ा होकर मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा श्रद्धा सुमन अर्पित किये। किसान नेता अशोक प्रसाद सिंह ने कहा कि किसान समस्याओं में पैदा होते हैं और समस्याओं में ही दम तोड़ देते हैं। उनकी अनंत समस्या है, परंतु समस्याओं की लंबी फेहरिस्त होने पर मांग का महत्व घट जाता है। इसलिए मात्र 21 सूत्री मांगों का प्रस्ताव किसानों के विशाल कन्वेशन में उन्होंने पेश किया। उन्होंने स्वामी सहजानंद सरस्वती के उस्तूं, उनके सपनों की चर्चा करते

हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला। किसान नेता दिनेश सिंह ने आंदोलन की रूपरेखा पेश करते हुए 15 जुलाई तक सभी जिलों की संयुक्त बैठक आयोजित करने। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक सभी प्रखंडों में संयुक्त बैठक एवं किसानों के मांगपत्र पर कन्वेशन आयोजित करने। 23 सितंबर

किसानों को ललकारा।

दोनों प्रस्ताव पर किसान नेता रामायण सिंह, अनिल कुमार सिंह, वी वी सिंह, बाल गोविंद सिंह, गोपाल कृष्ण, देव कुमार, रामनरेश महतो, रामकिशोर झा, प्रो कमला सिंह, अभिमन्यु कुमार, प्रमोद सिंह, गांधीजी, नागेश्वर यादव, त्रियंबकराज, गोपाल कुमार आदि ने अपने विचार व्यक्त किया। कन्वेशन में भाग ले रहे बिहार के 35 जिलों से आए हजारों प्रतिनिधियों ने करतल ध्वनि के साथ दोनों प्रस्ताव का समर्थन किया। इस अवसर पर किसान नेता मनोज मिश्रा ने अपने क्रांतिकारी गीतों से लोगों में एक नया क्रांतिकारी भावना पैदा की। सभी लोगों ने स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की मूर्ति पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा समारोह का समाप्त किया।

पेज 3 से जारी....

जनता के पैसे के बैंकों के माध्यम से ...

देने के नियमों को और अधिक उदार बना दिया गया, यदि ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक होती, तो नुकसान होता। अन्य जमाओं (प्रावधान) के मुनाफे से ब्याज और मूल राशि की भरपाई की गई, यदि किसी बड़े ऋण की वसूली की संभावना नहीं थी, तो उन्हें बैंकों की किताबों से हटा दिया गया, जिससे बैंकों की बैलेंस शीट साफ और लाभदायक हो गई, ताकि जमाकर्ताओं और खाताधारकों के लिए आकर्षक दिख सके। बैंक बड़े ऋण बकाएदारों की संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं और बकाया ऋण और ब्याज की वसूली करने का प्रयास करते हैं। लेकिन चूंकि इतनी बड़ी संपत्तियों के लिए बहुत सारे खरीदार नहीं हैं, इसलिए वे बहुत कम बोली लगाते हैं या सिंडिकेट बनाते हैं जो किसी भी बोली को रोकते हैं, जिससे ऋण की वसूली में और अधिक कठिनाइयां होती हैं। दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) से भी ऋणों की वसूली में कोई खास मदद नहीं मिली है। मई 2023 में आईबीसी की संहिता,

बाजार उधारी 12.19 लाख करोड़ रुपये के लगभग थी।)

कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कानूनों को बदल–बदल सकता है और अपने गलत कार्यों को भी वैध ठहरा सकता है। लेकिन जब इन कार्यों को नैतिकता के चश्मे से देखा जाता है, तो कई मुद्दे सामने आते हैं, जिन्हें एक राष्ट्र के रूप में हम टाल नहीं सकते। जब कोई अपने लेन–देन में वित्तीय समझौता करता है, तो वह करोड़ों बैंक जमाकर्ताओं के साथ अन्याय कर रहा है और इसलिए, यह न तो कानून में और न ही सामाजिक नैतिकता में स्वीकार्य है। इसे देखते हुए आरबीआई ने जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों से समझौता कर बकाया कर्ज का निपटान करने की जो अधिसूचना जारी की है, उसने पूरे देश को आश्चर्यचकित कर दिया है। क्योंकि, जैसा कि पहले कहा गया था, उसी आरबीआई ने 2019 में स्पष्ट रुख अपनाया था कि जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

बदली हुई परिस्थिति के आलोक में कुछ प्रश्न सामने हैं, जो इस प्रकार हैं:

1. किसकी राय और किसके कहने पर पुरानी पोजिशन बदली गयी?

2. यदि ऋण समझौतों का सम्मान नहीं करने वालों को छोड़ा जा रहा है, तो ऋण चुकाने वाले मूर्ख लग सकते हैं।

3. क्या कोई ऐसा व्यवसाय चलाएगा जिसमें आप 100 करोड़ रुपये का निवेश करें और बदले में 17 करोड़ रुपये वापस पाएं? क्या बैंक व्यापारिक कंपनियां नहीं हैं?

4. प्रत्येक बैंक एक अलग व्यवसाय है और उसके निदेशक मंडल बाजार में प्रत्येक व्यावसायिक इकाई का विवरण जानता है। तो फिर इन बोर्डों ने खाताधारकों का पैसा क्यों उड़ाया?

5. क्या किसी निदेशक मंडल, स्वतंत्र निदेशक आदि ने खाताधारकों, जमाकर्ताओं की चल रही गतिविधियों से अवगत कराया?

6. क्या निदेशकों की नियुक्ति में यह शर्त लगाना उचित नहीं होगा कि यदि गलत निर्णयों के कारण बैंकों को घाटा होता है, तो सबसे पहले निदेशक घाटे को वहन करेंगे?

(निम्नलिखित एक उदाहरण विवर्ण का है: कपास व्यापार में अनुभवी एक व्यक्ति, कपास सहकारी विपणन महासंघ का विपणन प्रबंधक बन गया। उसने महासंघ से कहा कि मुझे अपने निर्णय लेने की अनुमति दें और मुझे वेतन तभी दें जब मैं आपके लिए लाभ कमाऊं।) ये मामले न तो अर्थहीन हैं और न ही काल्पनिक। यदि लाखों खाताधारकों की मेहनत की कमाई को इतनी लापरवाही से संभाला जा रहा है, तो क्या हम उस प्रणाली को लोगों के पैसे की देखभाल करने वाली कुशल, जिम्मेदार कह सकते हैं? वर्तमान लेखक को नियमित रूप से उन मित्रों के फोन आते हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, कि क्या उनका पैसा बैंकों में सुरक्षित है और बैंकों का क्या होने वाला है... उन्हें बताया जा सकता है कि यदि बैंक सुरक्षित लेनदेन करते हैं, तो ही बैंक और लोगों की पैसा दोनों सुरक्षित रहेंगे।

मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी एकता जरूरी

"मोदी हटाओ, देश बचाओ" महीने भर लंबे अभियान का समापन कार्यक्रम 13 जून 2023 को पुडुचेरी में नए बस स्टैन्ड के पास आम सभा के साथ हुआ। आम सभा में जनतान्त्रिक, वाम और धर्मनिरपेक्ष दलों के नेता भी शामिल थे।

सभा की अध्यक्षता राज्य सचिव ए एम सलीम ने की, इस आम सभा से पूर्व पार्टी राष्ट्रीय परिषद के "मोदी हटाओ देश बचाओ" के आवान पर समस्त पुडुचेरी के 15 केंद्रों और करईकल जिले में 25 मई से 12 जून के बीच जन सभाएं की गई थीं।

समापन कार्यक्रम में समिलित भाकपा राष्ट्रीय सचिवमण्डल सदस्य डा. के नारायणा ने कहा कि "मोदी हटाओ देश बचाओ" केवल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नारा नहीं है बल्कि यह जनता का नारा है और जो भी भाजपा सरकार के कुशासन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, उन सभी नारा होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के अहितकर शासन में निर्वाचन आयोग समेत सभी वैधानिक निकायों पर भाजपा

सरकार का नियंत्रण है जबकि इन सभी निकायों को निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए।

डा. नारायणा ने केंद्र पर राज्यपाल के पदों को दुरुपयोग का आरोप लगते हुए कहा कि राज्य सरकारों के अधिकारों को हड्डपने के लिए मोदी सरकार राज्यपाल के पद पर अपने विश्वासपात्रों को बैठा रहे हैं। दिल्ली सरकार की विधायी और कार्यकारिणी शक्तियों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान न करने और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करने के लिए अध्यादेश लाने के लिए उन्होंने मोदी सरकार की निंदा की। उन्होंने कहा कि राज्यपाल जनता द्वारा निर्वाचित नहीं किए जाते वे राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं और राज्यपालों को निर्वाचित सरकारों के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए।

डा. नारायणा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह मोदी के नजदीकी कॉर्पोरेट घरानों को बजटीय अनुदान और टैक्स रियायातें दे रही है और इस सरकार के पास

आई दिनेश पोन्नेया

युद्धपथ पर खड़े किसानों की न्यायसंगत मांगों के लिए धन नहीं है। बंदरगाह, हवाईअड्डे और भारतीय जीवन वीमा निगम पर लगा जनता का पैसा प्रचलन तरीके से अडानी को दिया जा रहा है। कोई यह कह सकता है कि मोदी का अपना कोई परिवार नहीं है और इसलिए उन्हें भ्रष्टाचार में लिप्त होने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनके शासन में 30 कारोबारियों ने जनता का धन लूटा है, जिन्हे देश छोड़ने के लिए आजाद रखा गया था।

भाजपा के नौ साल के शासन के दौरान सभी अनिवार्य वस्तुओं के दाम आसमान पर हैं। रसोई गैस सिलेंडर का दाम 410 रुपए से बढ़कर 1210 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया है। उन्होंने कहा कि इस अवधि में पेट्रोल और डीजल के दामों में कई गुना वृद्धि हुई है। डा. नारायणा ने कहा कि देश चौराहे पर है। मोदी के शासन में, हमारे देश के जनतान्त्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर खतरा है। देश की संघीय

व्यवस्था दाव पर है।

यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रपति को भी नहीं छोड़ा गया। नए निर्मित संसद भवन के उद्घाटन के लिए संसद के सर्वोच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति को न कहने से मोदी ने देश के संविधान, महिलाओं और आदिवासियों के खिलाफ काम किया है। नारायणा ने कहा हो सकता है कि भाजपा का राजनीतिक एजेंडा मोदी को राष्ट्रपति बनाने का और यहाँ अमरीकी संसदीय मॉडल को लागू करने का है।

सभा को संबोधित करते हुए डा. नारायणा ने अपने भाषण में सभी धर्मनिरपेक्ष और जनतान्त्रिक ताकतों से मोदी की प्रतिगामी नीतियों का प्रतिरोध करने का और देश के धर्मनिरपेक्ष, जनतान्त्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आगामी चुनावों में संयुक्त रूप से भाजपा सरकार को अपदस्थ करने का आग्रह किया।

भाकपा राज्य सचिव ए एम सलीम ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार वादों को निभाने में असफल रही है। राज्य की भाजपा

सहयोगी एनआर कॉर्प्रेस सरकार का राज्य के विकास और राज्य के अधिकारों से कोई सरोकार नहीं है। सरकार द्वारा संचालित टेक्स्टाइल मिलों जो कि रोजगार का स्वर्ग थी उन्हें बंद कर सरकार ने हजारों पब और रेस्टरों बार के दरवाजे खोल दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पुडुचेरी में "देश बचाओ, भाजपा हटाओ" अभियान को भाजपा के राष्ट्रविरोधी शासन का पर्दाफाश करने के लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया।

आम सभा में कॉर्प्रेस पार्टी से पुडुचेरी के पूर्व मुख्य मंत्री वी. नारायणसामी, पुडुचेरी के विपक्ष के नेता और डीएमके के संयोजक आर शिव, भाकपा (मा) राज्य सचिव आर राज्ञगम, वीसीके के मुख्य सचिव देवा पोडिलन, पूर्व भाकपा मंत्री, भाकपा राज्य कार्यकारिणी सदस्य, भाकपा (माले) से मोतीलाल, डीके से शिव वीरमणी, आई यू एम एल से उमर फारुक, एमएमके से वाई मुश्तक दिन आदि ने जन सभा को संबोधित किया।

तंजीमें इंसाफ का तेलंगाना राज्य सम्मेलन

समान नागरिक संहिता से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रही भाजपा

भाकपा के राष्ट्रीय सचिव, ऑल इण्डिया तंजीमें इंसाफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद सेयद अजीज पाशा ने कहा कि इस देश के लोगों को समान नागरिक संहिता को हथियार बनाकर भारतीय समाज को सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकृत करने की भाजपा की साजिश के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अजीज पाशा तेलंगाना राज्य तंजीमें इंसाफ के तीसरे राज्य सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर 26 जून को बोल रहे थे। इसके अलावा भाकपा के राज्य सचिव और पूर्व विधायक के संबासिवा राव ने भी सम्मेलन को संबोधित किया।

अजीज पाशा ने आगे संबोधित



करते हुए कहा है कि भाजपा और संघ परिवार मुसलमानों को निशाना बनाकर उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण तरीके से प्रचार कर रहे हैं क्योंकि ऐसा प्रचार किया जाता है कि मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह अधिक है। अगर ऐसा है तो देश की जनता को विधि आयोग के जनगणना के आंकड़ों पर गैर करना चाहिए। भारत सरकार की जनगणना के आधार पर विधि आयोग द्वारा जारी नोट के अनुसार विभिन्न समुदायों में बहुविवाह का प्रचलन इस प्रकार है। आदिवासियों में बहुविवाह 15.25 प्रतिशत, बौद्धों में 7.9 प्रतिशत, जैनियों में 6.72 प्रतिशत, हिंदुओं में 5.80 प्रतिशत है लेकिन मुसलमानों में यह

केवल 5.70 प्रतिशत है। संघ परिवार का मुस्लिम अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का दुष्प्रचार "हम पांच और हमारा पचास" दुर्भावनापूर्ण है लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अजीज पाशा ने आलोचना करते हुए कहा कि

यह प्रचार लोगों को सच्चाई और तथ्यों से भटकाने के अलावा और कुछ नहीं है। तेलंगाना भाकपा राज्य सचिव और पूर्व विधायक के संबासिवा राव ने संबोधित करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि भाजपा 2024 में आगामी चुनावों में सत्ता में आती है, तो या तो वह वर्तमान संविधान को खत्म कर देगी या संविधान में हिंदू समर्थक संशोधन लाएगी। वे संशोधन हिंदुत्व के हितों की पूर्ति करेंगे। तेलंगाना में भाकपा चिंतित है कि वह मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए अपना अधिकात्म समर्थन देगी। हालाँकि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित विपक्षी दल 2024 में आगामी चुनावों में

भाजपा और उसके सहयोगियों को उचित सबक सिखाएंगे। राज्य सम्मेलन ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए 12

शुरूआत में मुशयरे में कई मुस्लिम शायरों और आम लोगों और महिलाओं ने शिरकत की।



मोदी सरकार की योजनाओं की घोषणाओं और विफलताओं के नौ साल

सरकारी खर्च पर उठे सवाल

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'बेटी बचाओ' अभियान पर संसद की समिति के अनुसार राज्यों ने इस योजना के फंड का करीब 156 करोड़ रुपये ही सही उद्देश्यों पर खर्च किया है। समिति ने कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के संदेश को लोगों के बीच फैलाने के लिए मीडिया अभियान चलाने की आवश्यकता का समझती है, पर इस योजना के उद्देश्य को संतुलित करना भी उतना ही जरूरी है। समिति ने सुझाव दिया कि सरकार को महिला एवं बाल कल्याण विभाग को राज्य केंद्र शासित प्रदेश के साथ मिलकर फंड की मदद से बेटियों की पढ़ाई और उनके स्वास्थ्य से संबंधित इंतजाम करने चाहिए।

कहीं स्कूल दूर, तो कहीं गरीबी से बढ़ा ड्रॉपआउट

बेटियों के अधिकारों की अगर बात करें तो ये कहना बेहद मुश्किल है कि कितना सुधार हो पाया है। बेशक सरकार की ओर से जागरूकता अभियान और तरह-तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं पर जब तक समाज से बेटियों और बेटों के बीच भेदभाव खत्म नहीं हो पाएगा, तब तक बेटियों को बराबर का दर्जा नहीं मिल पाएगा। तब तक किसी भी योजना को सफल कहना काफी हद तक गलत ही होगा।

कई राज्य ऐसे हैं जहां या तो स्कूल दूर है या फिर परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण लड़कियों का ड्रॉपआउट बढ़ा है। कई महिलाएं मजदूर हैं। इसलिए बेटियां घर व खेत का काम करती हैं। कुछ बड़ी होने पर उन्हें भी मजदूरी करनी पड़ती है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

भारत के छोटे उद्यमियों की सहायता करना भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और समृद्धि में सहायक बनने का सबसे बड़ा माध्यम है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य है 'जिसके पास धन नहीं है, उसे धन उपलब्ध कराना' है, लेकिन सवाल इस योजना पर भी उठ रहे हैं। इसका आशय यह नहीं है कि यह फ्लॉप हो गई या अब सफल नहीं हो सकती।

इस योजना के तहत महिला स्व-सहायता समूहों में से ऋण लेने वालों में जो ईमानदारी और निष्ठा देखी गई है, वह किसी अन्य क्षेत्र में विरले ही दिखती है। इसलिए यह योजना सही है, जरूरत है कुछ बदलाव की।

इस प्रयास से स्थापित वित्तीय प्रणालियां जल्द ही कामकाज के मुद्रा मॉडल को अपना लेंगी यानी ऐसे उद्यमियों को सहायता देंगी, जो कम से

कम राशि में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दे सकें। जरूरत है कि हम बेरोजगारों के भले के लिए सोचें, न कि दुष्परिणामों को लेकर बैठे रहें। हमारे देश में ऐसा महसूस होता है कि बहुत सी चीजें सिर्फ दृष्टिकोण के आसपास मंडराती हैं, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग होती है।

बड़े उद्योगों द्वारा रोजगार के ज्यादा अवसर सृजित किए जाने संबंधी दृष्टिकोण भी इसी तरह से गलत है। वास्तविकता पर नजर डालने से पता चलता है कि बड़े उद्योगों में सिर्फ 1 करोड़ 25 लाख लोगों को रोजगार मिलता है, जबकि देश के 12 करोड़ लोग छोटे उद्यमों में काम करते हैं।

इसी के चलते यह योजना बेरोजगारों के बीच नहीं आ पाई। यही

महेश राठी

नियंत्रण ढांचे पर वापस आ गई, और आश्वर्यजनक रूप से, क्रेडिट और नौकरी की वृद्धि देने में विफल रही।

एक वित्तीय फर्म के लिए छोटे व्यवसायों को उधार देना महंगा है। प्रारंभिक मूल्यांकन लागतें अधिक हैं, जोखिम और व्यावसायिक योजनाओं का आकलन करना पड़ता है, और इसलिए प्रति ऋण लेनदेन लागत अधिक होती है। प्रारंभिक मूल्यांकन लागतों के अलावा, ऋणों की निगरानी, ब्याज और मूलधन एकत्र करने की लागत भी अधिक होती है।

प्रतिस्पर्धा का अभाव

बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय

ऋण देने का सवाल आया, तो सरकार ने एक नीति तैयार की। बैंकों से छोटे कारोबारियों को प्राथमिकता के आधार पर कर्ज देने को कहा गया। लघु उद्योग के लिए ऋण आरबीआई के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण ढांचे का हिस्सा थे।

बदले में यह बैंकिंग नीति ढांचे का हिस्सा था जो यह तय कर रहा था कि घरेलू बचत का कितना हिस्सा सरकार, कृषि और निर्यात में जाएगा। बांड बाजार जैसे अन्य रास्तों की कमी ने बड़े कर्जदारों को बैंकों में जाने के लिए प्रोत्साहित किया। और, बैंक जो जोखिम लेना पसंद नहीं करते थे, वे छोटे व्यवसायों की तुलना में ट्रिपल ए-रेटेड कंपनियों को पसंद करते थे। इस माहौल में, छोटे व्यवसायों के लिए ऋण अनिवार्य करना पड़ा।

चलता है कि बैंक शाखाओं ने '50 मीटर नियम' और 'व्यक्तिगत संबंधों' के आधार पर ग्राहकों को चुना। 50 मीटर का नियम उन ग्राहकों को ऋण देने का था जो बैंक शाखा के 50 मीटर के दायरे में थे। कई मामलों में, उन्हें इस बात की परवाह किए बिना ऋण की पेशकश की गई थी कि वे उन्हें चाहते हैं या नहीं।

लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, शाखा के परिचित ग्राहकों को प्राथमिकता दी गई और उनकी जरूरतों के बावजूद 10,000 रुपये से 50,000 रुपये के पूर्व निर्धारित ऋण की पेशकश की गई। जो लोग खुद बैंकों के पास पहुंचे, जो अब तक अनजान थे और दूर रहते थे, उन्हें सबसे कम तरजीह दी गई।

मुद्रा मांगने के लिए बैंक जाने से आपको शायद ही कभी ऋण मिलेगा।

अधिकांश ऋण खाते 'शिशु' श्रेणी में थे और औसत ऋण आकार 52,739 रुपये था। ये स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं को दिए गए ऋणों के समान थे, जो अब मुद्रा ऋणों के लिए योग्य थे।

नोटबंदी के कारण पटरी से उतरी

इस माहौल में विमुद्रीकरण अभियान आया जिसके तहत छोटे व्यवसायों को गंभीर नकदी प्रवाह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की अनुपालन लागत के कारण हुए व्यवधान से उनका व्यवसाय मुश्किल हो गया था।

कई अपना कर्ज नहीं चुका पाए। जबकि आरबीआई ने इस संबंध में प्रावधानों में ढील दी, नए लघु व्यवसाय ऋणों की वृद्धि धीमी हो गई। इसके अलावा, आईएल एंड एफएस संकट का मतलब था कि एनबीएफसी धन जुटाने में सक्षम नहीं थे। इस प्रकार, छोटे व्यवसायों के लिए एनबीएफसी ऋण वृद्धि धीमी हो गई।

ऐसे समय में जब बड़ी परियोजनाओं में निवेश वैशिक वित्तीय संकट के प्रभावों से उबर नहीं पाया था, छोटे व्यवसायों को ऋण रोजगार वृद्धि प्रदान कर सकता था। इन्हीं कारणों से यह योजना भी अपने तय लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाम रही।

स्मार्ट सिटी योजना; लक्ष्यों से दूर योजना

सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजना एक ऐसी योजना है जिसका प्रचार मोदी सरकार ने खूब जोर शोर से किया। ऐसा प्रचार किया गया कि मानो इससे शहरों का ही नहीं पूरे देश का कायाकल्प हो जायेगा। वैसे भी जुमलों से लेकर विकास के दावों तक मोदी

कंपनियां (एनबीएफसी) छोटे व्यवसायों को ऋण देना पसंद करती हैं यदि उनका व्यवसाय मॉडल आकर्षक है। इसके अलावा, निर्यात उनके आकार, ब्याज दर, संपार्शिक लेने या क्रेडिट रजिस्ट्री का उपयोग करने की क्षमता आदि पर निर्भर करता है।

यदि ग्राहकों को प्राप्त करने और बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा है, तो लघु व्यवसाय ऋणों के लिए बाजार फलता-फूलता है। एक बाजार अर्थव्यवस्था में, आगे का रास्ता यह होता कि अधिक बैंक लाइसेंस देकर प्रतिस्पर्धा शुरू की जाती ताकि बैंक क्रेडिट का विस्तार हो सके।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दौर से ही, भारत ने एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को लाभ कमाने वाले व्यवसाय के बजाय नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करना चुना। इसके अलावा, निजी बैंकों को हतोत्साहित किया गया था। बैंकिंग के कारोबार में आमतौर पर बैंकों द्वारा जो किया जाता था, वह डिक्टेट द्वारा किया जाता था।

नतीजतन, जब छोटे व्यवसायों को

स्माल व्यवसाय लगभग हर देश में सबसे बड़े नियोक्ताओं में से हैं। भारत में, 51 मिलियन औपचारिक और अनौपचारिक छोटे व्यवसाय हैं। वे 117 मिलियन लोगों को रोजगार देते हैं, या श्रम शक्ति का लगभग 40 प्रतिशत। फिर भी, केवल लगभग 5 मिलियन छोटे व्यवसायों के पास लघु ऋण तक पहुंच है।

अनफंडेड को फंड करने के लिए— यह धारणा कि इन छोटे व्यवसायों को असुरक्षित, उपलब्ध कराया जाना चाहिए— सही उद्देश्य है। हालांकि, जब सरकारी योजनाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लक्ष्यों के माध्यम से लागू किया गया, तो नीति पुराने कमाड़ और

माइक्रोसेव की एक रिपोर्ट से पता



सरकार का हर काम ऐतिहासिक ही होता है। इस योजना के तहत जनवरी 2023 तक 68 स्मार्ट शहरों ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया है तथा इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए योजना की अवधि को इस साल जून तक बढ़ाया गया है। यह आंकड़े स्वयं संसद की एक स्थायी समिति की रिपोर्ट में सामने आये हैं।

संसद की समिति ने सरकार से पीछे चल रहे योजना के वास्तविक और वित्तीय दोनों लक्ष्यों को अतिरिक्त दिये गये समय में पूरा करने के लिए तेजी से प्रयास करने को कहा है। संसद में 20 मार्च को पेश जनता दल यू के सांसद राजीव रंजन सिंह की अध्यक्षता वाली आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रिपोर्ट कहती है कि समिति इस बात को संज्ञान में लेती है कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत चयन का अंतिम दौर जनवरी 2018 में हुआ था और इसलिए पांच साल की निर्धारित अवधि पूरी हो चुकी है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जहां तक मंत्रालय के वित्तीय आवंटन का संबंध है, मिशन को दी गई 48,000 करोड़ रुपये की समग्र वित्तीय सहायता में 36,561 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इसमें से 33,012 करोड़ रुपये (कुल जारी राशि का 90 प्रतिशत) स्मार्ट सिटी योजना द्वारा उपयोग किए जा चुके हैं। समिति ने कहा कि योजना के तहत 100 स्मार्ट सिटी ने 2,05,018 करोड़ रुपये की परियोजना का प्रस्ताव किया था जिसमें से 1,81,349 करोड़ रुपये की 7821 परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अब तक 1,00,450 करोड़ रुपये की 5343 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसके अनुसार, स्मार्ट सिटी योजना के तहत शुरू की गई परियोजनाओं की शहर–वार वास्तविक प्रगति से यह पता चलता है कि विभिन्न शहरों के कार्य पूर्ण करने में बहुत अधिक अंतर है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि, एक ओर, 32 स्मार्ट शहरों ने मिशन के तहत कार्यान्वय के लिए नियोजित परियोजनाओं और कुछ मामलों में वास्तविक लक्ष्य से चार गुणा से भी अधिक संख्या में कार्य को पूरा कर लिया है। तो वहीं शेष 68 स्मार्ट शहरों को अभी भी परियोजना के लक्ष्यों को पूरा करना है जिसमें से कुछ शहरों का प्रदर्शन काफी निराशजनक और चिंताजनक है। समिति ने कहा कि ऐसे में पूरी की गई परियोजनाओं की कुल संख्या एक भ्रम पैदा करने वाली तस्वीर पेश करती है क्योंकि इसमें 32 बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्मार्ट शहरों द्वारा पूरी की गई अतिरिक्त परियोजनाओं को भी ध्यान में रखा गया है। रिपोर्ट के

अनुसार, समिति की राय है कि यदि पूर्ण की गई परियोजनाओं में से 'अतिरिक्त परियोजनाओं' की संख्या को हटा दिया जाता है तो 31 जनवरी 2023 की स्थिति के अनुसार मिशन के तहत पूर्ण की गई परियोजनाओं की वास्तविक संख्या अनुमानित संख्या से बहुत कम होगी। समिति ने कहा कि तथ्य यह है कि 31 जनवरी 2023 की स्थिति के अनुसार, 68 स्मार्ट शहरों ने मिशन के तहत अपने वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया, इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मिशन की अवधि जून 2023 तक बढ़ा दी गई है।

समिति ने इस बात के रेखांकित किया कि मंत्रालय को पिछड़ते स्मार्ट सिटी योजना को पूरा करने के प्रयास तेज करने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वास्तविक और वित्तीय दोनों लक्ष्यों को वास्तव में विस्तारित समय अवधि अर्थात् जून 2023 के भीतर प्राप्त कर लिया जाए। संसदीय समिति ने इसमें हुए अत्यधिक विलंब के कारणों का विस्तृत मूल्यांकन करने तथा इसका समाधान किए बिना और समय विस्तार नहीं देने की सिफारिश की है।

डिजिटल इंडिया मिशन; मंजिल से कोसो दूर

2014 में सत्ता हासिल करने में भाजपा ने डिजिटल संसाधनों का या कहे प्रौद्योगिकी कर जमकर इस्तेमाल किया। सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार डिजिटलीकरण करने के मकसद से डिजिटल इंडिया मिशन की शुरूआत की। बगेर किसी पूर्व तैयारी के और सुनियोजित योजना के डिजिटल इंडिया मिशन की शुरूआत की गयी और नतीजा मोदी की बाकि योजनाओं जैसा ही रहा। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की पहुंच बढ़ाने की दौड़ में भारत का प्रदर्शन पिछले साल तक काफी खराब रहा है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने 189 देशों को शामिल करते हुए 'द स्टेट ऑफ ब्रॉडबैंड 2015' नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार, ब्रॉडबैंड पहुंच के मामले में भारत की रैंकिंग 2013 के मुकाबले 2014 में छह अंक घिरकर 131 पर पहुंच गई। मोबाइल इंटरनेट के मामले में भारत 2013 में 113वें पायदान पर था।

वहीं 2014 में वह 155वें पायदान पर खिसक गया। भारत की स्थिति श्रीलंका और नेपाल से भी नीचे रही, जिनकी रैंकिंग क्रमशः 126 और 115 थी। रिपोर्ट के अनुसार, घरों में इंटरनेट कनेक्शन में बढ़ोत्तरी के बावजूद 133 विकासशील देशों में भारत पांच पायदान खिसक कर 80 पर आ गया था। रिपोर्ट के ये नतीजे उन चुनौतियों की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसका समाना मोदी सरकार की डिजिटल

इंडिया परियोजना कर रही है। मोदी सरकार की परियोजना का मकसद था कि 2019 तक पूरे देश में तेज रफ्तार इंटरनेट मुहूर्या कराकर डिजिटल विभाजन को कम किया जाए। परंतु आज भी भारत की बहुमत आबादी इस परियोजना के बारे में अथवा डिजिटलीकरण के बारे में अनजान है।

डिजिटल इंडिया मिशन योजना हर क्षेत्र में डेलाइन से काफी पीछे चल रही है। इसमें सबसे बड़ी बाधा है हिंसाग्रस्त प्रदेशों में अंडरग्राउंड नेटवर्क बिछाना, जैसे— अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, भारत प्रशासित कश्मीर, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड आदि। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच सहमति का अभाव भी बाधा पैदा कर रहा है और इस पर निरक्षरता, गरीबी और कुशल श्रमशक्ति का अभाव भी भारी पड़ रहा है। साथ ही गांवों और कस्बों के अधिकांश स्कूल भी कंप्यूटर और कंप्यूटर में दक्ष शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। मोबाइल फोन के मामले में भारत एक बड़ा बाजार है लेकिन मोबाइल उपकरणों के मार्फत अच्छी इंटरनेट स्पीड हासिल करना अभी दूर की कौड़ी है। आंकड़े दिखाते हैं कि दुनिया में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली तीसरी सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद भारत इंटरनेट स्पीड के मामले में 52वें स्थान पर है। यहां औसत स्पीड 1.5 से लेकर 2 एमबीपीएस है, जबकि दक्षिण कोरिया और जापान जैसे अन्य विकसित एशियाई देशों में इंटरनेट स्पीड क्रमशः 14.2 और 11.7 एमबीपीएस है।

5जी लांच को लेकर किया गया खासा प्रचार

अक्टूबर 2022 में भारत ने 5जी सेवाएं लांच की और इनकी लाँचिंग को लेकर जबरदस्त प्रचार किया। हालांकि इहें लांच करना एक साधारण मामला था। परंतु प्रधानमंत्री किसी भी मौके को अपने प्रचार का माध्यम बनाने से चुकते नहीं हैं और इस मामले में भी यही हुआ। इतना प्रचार इसे लेकर तब था जबकि दुनिया के द्वेषों देश इसे लेकर तब था जबकि दुनिया के द्वेषों देश इसे लांच कर चुके थे। 2019 से लगभग 70 देशों ने इसे लगभग 2,000 शहरों में लांच कर दिया था जब दक्षिण कोरिया ने इसके माध्यम कनेक्टिविटी के नए युग की शुरूआत की थी।

भारत में 5जी को शुरू करने के प्रयासों काफी पिछड़ा रहा था। जिसमें सबसे बड़ी बाधा एयरवेव बिक्री के लिए उच्च आरक्षित कीमतें थीं। 5जी तकनीक के लिए आवश्यक 700 मेगाहर्ट्ज बैंड की कीमत इतनी अधिक

थी कि मार्च की नीलामी में इसे कोई बोली नहीं मिली और यहां तक कि हालिया नीलामी में भी केवल एक कंपनी, मार्केट लीडर मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ही बोली लगा पाई। सरकार द्वारा दरें कम करने के बावजूद मांगी जा रही कीमत काफी बड़ी थी। रिलायंस जियो द्वारा छेड़े गए गलाकाट टैरिफ युद्ध के बाद टेलीकॉम कंपनियों को नुकसान हो रहा है। अधिकांश ऑपरेटर दिवालिया हो गए हैं और नौकरी छोड़ चुके हैं या विलय में चले गए हैं। परंतु अंबानी का जियो एकाधिकार की दौड़ में लगा है।

5जी के नहीं होने का कारण भारत में खराब बुनियादी दांचे का होना है और इसके लिए देश में पर्याप्त फाइबर नेटवर्क ही नहीं है। दरअसल, 5जी एक नए प्रकार का नेटवर्क प्रदान करता है जो मोबाइल और अन्य उपकरणों से लेकर वस्तुओं और मशीनों तक लगभग सभी को एक साथ जोड़ सकता है। यह जिस विशाल नेटवर्क क्षमता की शुरूआत कर सकता है उसका मतलब है कि अधिक विश्वसनीयता होगी और डेटा भेजे जाने और प्राप्त होने के समय के बीच लगभग कोई अंतराल नहीं होगा। यह सब 4जी के साथ संभव नहीं है, जो देश में उपलब्ध सबसे ज्यादा स्पीड वाला नेटवर्क है। और जब मोदी सरकार 5जी के लिए यहां नीतिगत उलझनों को सुलझा रही थी, वैशिक कंपनियों के एक समूह, जिनमें ज्यादातर चीनी थे, ने 5जी और यहां तक कि 6जी पर बौद्धिक संपदा अधिकारों पर कब्जा कर लिया था। 6जी जो कि अभी भी एक दशक दूर है।

नए युग के नेटवर्क में वर्चस्व के लिए दुनिया भर में बड़ी लड़ाई चल रही है और भारत वैशिक पेटेंट परिवृश्य में जरा भी जगह नहीं बना पाया है। नई पीड़ी के नेटवर्क पर बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) क्यों मायने रखते हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि अगली औद्योगिक क्रांति में तकनीकी अभिसरण में वृद्धि देखी जाएगी क्योंकि कनेक्टिविटी को यांत्रिक उत्पादों में एकीकृत किया गया है, जैसे कि ऑटोमोबाइल, जो ऐसा उद्योग प्रतीत होता है जो इस संदर्भ में सबसे अधिक चर्चा में है। अभी, कारों में कनेक्टिविटी मॉड्यूल महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य के कनेक्टेड वाहन समग्र रूप स

संयुक्त विपक्ष को देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन का नाम दिया जायेगा

12 जुलाई को शिमला में विपक्षी राजनीतिक पार्टियों की संयुक्त बैठक के रणनीति सत्र में अपने सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम और अपनी चुनावी नीति के व्यापक प्रतिमान को सार्वजनिक करने से पहले ही विपक्षी नेताओं ने अपने प्रयास को एक विशिष्ट वैचारिक चरित्र देने और इसे देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन के रूप में पहचानने का फैसला किया है। महत्वपूर्ण यह कि यह प्रस्ताव औपचारिक घोषणा के ठीक 48 घंटों के भीतर सामने आया।

उनके प्रयास को एक निश्चित संगठनात्मक चरित्र देने के लिए दूसरे सम्मेलन शिमला में आयोजित किया जायेगा। विपक्षी नेताओं के इस कदम से यह स्पष्ट हो गया है कि वे दक्षिणांशी भाजपा और आरएसएस के साथ लंबी वैचारिक लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। पुराने यूपीए को पुनर्जीवित करने के बजाय उनका नया नाम देना एक स्पष्ट और जोरदार संदेश देता है कि वे संघर्ष को भगवा ब्रिगेड की माद में ले जाने का इरादा रखते हैं।

अब तक आरएसएस और भाजपा विपक्षी नेताओं को राष्ट्रविरोधी करार देकर उन पर हर तरह का दमन और अत्याचार करती रही है। नया शब्द 'देशभक्त' अपने राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्रवाद का उपयोग करने के आरएसएस-भाजपा के राजनीतिक आधिपत्य के खिलाफ सीधे टकराव के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। मिशन को हासिल करने के लिए, जैसे अर्जुन ने लौकिक मछली की आंख पर निशाना साधा है।

विपक्ष बंगाल, बिहार, दिल्ली, तमिलनाडु, पंजाब, झारखण्ड, महाराष्ट्र, हिमाचल, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक में फैली सीटों पर निशाना साध रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बिहार की 40 सीटों में 17, छत्तीसगढ़ की 11 में 9, हिमाचल प्रदेश की 4 में 4, झारखण्ड की 14 में 11, कर्नाटक की 28 में 25, महाराष्ट्र की 48 में 23, पंजाब की 13 में 2, राजस्थान की 25 में 24, तमिलनाडु की 39 में 0, पश्चिम बंगाल की 42 में 18 और दिल्ली की 7 में 7 सीटें जीती थीं। विपक्षी नेताओं को अन्य राज्यों में भी अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है, लेकिन अगर वे इन राज्यों में पर्याप्त सीटें जीतने में कामयाब रहे, तो वे भाजपा को सत्ता से बाहर करने में सफल होंगे।

यद्यपि भाजपा पारिस्थितिकी तंत्र और कुछ दक्षिणांशी विशेषज्ञों द्वारा यह धारणा बनायी जा रही है कि मौजूदा राजनीतिक स्थिति अभी भी नरेंद्र मोदी

के तीसरी बार सत्ता में आने के लिए अनुकूल है, वे यह भूल जाते हैं कि राजनीति स्थिर नहीं है और 2023 में राजनीतिक स्थिति अस्थिर ही बनी रहेगी। कोई पुलवामा तत्व नहीं है। प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों करना है। लोगों का विश्वास जीतने के लिए यह महत्वपूर्ण है।

किसी भी अन्य स्थिति में अमित शाह ने मणिपुर नरसंहार पर चर्चा के लिए विपक्षी नेताओं की बैठक नहीं बुलाई होती। शाह का यह दृष्टिकोण इस धारणा को पुष्ट करता है कि भाजपा नेतृत्व घबड़ा गया है और यह प्रबल भावना है कि इस बार उनकी चालें और जुमले

अरुण श्रीवास्तव

जायेगी। नेताओं का प्रयास एकता अभ्यास को एक संस्थागत चरित्र प्रदान करना है। लोगों का विश्वास जीतने के लिए यह महत्वपूर्ण है।

गठबंधन टूटने और साझेदारों द्वारा एक-दूसरे पर अरोप लगाने की पिछली घटनाओं ने लोगों को ऐसी किसी भी कवायद पर अविश्वास करने पर मजबूर कर दिया है। उनके अभ्यास को पुष्ट करता है कि भाजपा नेतृत्व घबड़ा गया है और यह प्रबल भावना है। हालांकि राहुल गांधी विपक्षी नेताओं

में छोटे दृष्टिकोण हो सकते हैं लेकिन उन पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक पार्टियाँ एक साथ आयी हैं, वे किसी भी मुद्दे पर 'सामूहिक रूप से' निर्णय लेने में सक्षम हैं।

यहां तक कि नीतीश भी इस बात से नाखुश थे कि आप उस अध्यादेश पर नाराज हो गयी हैं, जो दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करने का प्रयास करता है। भाकपा (एमएल) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप इस मुद्दे को दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस के साथ प्रतिद्वंद्विता के चश्मे से देख

करने को कहा था। उन्होंने कहा कि अध्यादेश की निंदा में सभी दल एकमत थे, लेकिन आप नेतृत्व को इस मुद्दे को व्यापक संदर्भ में रखना चाहिए। यह भाजपा सरकार द्वारा संविधान और संघवाद के सिद्धांत पर हमलों के बारे में है, यही कारण है कि हम सभी ने अपने मतभेदों को भुला दिया और हाथ मिला लिया।

केजरीवाल के रुख के विपरीत, नेताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी नेताओं की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के दोस्तों ने परिपक्वता दिखायी। उन्होंने याद दिलाया कि आप ने संसद में उस विधेयक के पक्ष में मतदान किया था, जिसने इस उत्तरी राज्य का विशेष दर्जा, उसका राज्य का दर्जा और उसकी अखंडता छीन ली थी। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने बैठक में अध्यादेश का मुद्दा उठाया। अध्यादेश की आलोचना करने से कोई नहीं हिचकिचाया। मुझे उनकी पार्टी द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाने के पक्ष में मतदान करने के प्रति कोई शिकायत नहीं है। हालांकि बैठक का एजेंडा विपक्षी एकता था। जैसे-जैसे विपक्षी दल महत्वपूर्ण शिमला सम्मेलन के लिए तैयार होंगे, अधिक आंतरिक चर्चाएँ होंगी, नये गैर-भाजपा दलों से संपर्क किया जायेगा और शिमला चर्चा को और अधिक उत्पादक बनाने के लिए सभी प्रयास किये जायेंगे।

नीतीश कुमार, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और शरद पवार अहम भूमिका निभायेंगे। उनका दृढ़ संकल्प है कि शिमला सम्मेलन 2024 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्ष को ऐतिहासिक समझौते का आधार बनाना चाहिए। (संवाद)



काम नहीं करेंगे। उनके मंसूबे उजागर हो गये हैं।

भाजपा को हराने का विपक्षी नेताओं का संकल्प बैठक में भाग लेने के लिए पटना पहुंचने से पहले ही रणनीति और कार्यक्रम का ब्लू प्रिंट तैयार करने के उनके कदम में भी प्रकट होता है। उन्होंने पहले ही एक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार चुनाव की रणनीति पर काम कर लिया था। जैसा कि कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे ने बैठक के बाद प्रेस को बताया कि राज्य विशेष में सबसे मजबूत पार्टी को चुनावी तंत्र को अंतिम रूप देने में प्राथमिकता दी जायेगी।

फिर भी इस नीतिगत निर्णय की औपचारिक घोषणा शिमला अधिवेशन में की जायेगी। शिमला सम्मेलन नीतियों और कार्यक्रमों की निरंतर निगरानी और समय-निर्धारण के लिए एक छोटी कोर समिति का गठन करेगा। कोर कमेटी को सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने और किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए राज्य स्तर की प्रमुख पार्टी के साथ बातचीत करने की जिम्मेदारी सौंपी

रहे हैं। उनका विचार था कि अध्यादेश देश के संघीय चरित्र पर हमला था। उन्होंने जोर देकर कहा कि आप की ओर से आधिकारिक बयान में यह कहना गलत है कि कांग्रेस ने बैठक में अध्यादेश का विरोध करने से इनकार कर दिया, जबकि कई पार्टियों ने ऐसा

मुक्ति संघर्ष पद्धि

चन्द्र की दर:

वार्षिक	: 350 रुपये
अर्द्धवार्षिक	: 175 रुपये
एक प्रति	: 7 रुपये
एजेंसी डिपोजिट	
प्रति कापी :	70 रुपये

खाता नाम: मुक्ति संघर्ष वीकली

बैंक: सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रेस एसिया ब्रांच

चालू खाता संख्या: 1033004704

आईएफसी कोड: सीबीआईएन 0280306

कापी मगाने के लिये लिखें:

व्यवस्थापक: मुक्ति संघर्ष साप्ताहिक

अजय भवन, 15-का, इन्द्रजीत गुजरा मार्ग

नयी दिल्ली-110002

नोट: डीडी और चेक केवल "मुक्ति संघर्ष साप्ताहिक" के नाम होना चाहिए।

झारखंड राज्य विस्थापित संघर्ष मोर्चा का राजभवन पर महा धरना

रांची: झारखंड राज विस्थापित संघर्ष मोर्चा की ओर से विस्थापित किसानों के हक और अधिकार के लिए झारखंड की राजधानी रांची में राजभवन के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन महाधरना दिया। अध्यक्षता झारखंड राज्य विस्थापित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने किया। मंच संचालन 'कर्णपुरा बचाओ, आजादी बचाओ' आंदोलन के नेता डॉ. मिथिलेश दांगी ने किया।

धरने में मुख्य रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव महेंद्र पाठक वरिष्ठ भाकपा नेता राजेंद्र प्रसाद यादव, बाबूलाल झा, जिला सचिव अजय कुमार सिंह, माकपा के राज्य सचिवमंडल के सदस्य सुरजीत सिन्हा, झारखंड राज्य किसान सभा के सचिव सुफल महतो, भाकपा माले के नेता देवकीनंदन बेदिया, महिला आयोग के पूर्व सदस्य वासबी किड़ो, रैयत विस्थापित संघर्ष मोर्चा के इकबाल अंसारी, बोकारो विस्थापित मोर्चा के गणेश महतो, गोंदल पुरा बचाओ संघर्ष समिति के अनिरुद्ध कुमार महतो, चतरा जिला के किसान बचाओ संघर्ष समिति के अर्जुन कुमार दांगी, भाकपा के वरिष्ठ नेता बनवारी साव, गयानाथ पांडे सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया।

पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि झारखंड के गठन 23 वर्ष बीत जाने के बाद भी राज्य में विस्थापन आयोग का गठन नहीं हुआ और ना ही विस्थापन नीति बनी। पूर्व में ही हजारों एकड़ जमीन कौड़ी के मूल्य में किसानों से जबरन ले ली गयी। चाहे एचईसी हो, बोकारो हो, पीटीपीएस हो, बीटीपीएस हो, पीटीपीएस, रोड या कई



तरह के खान और खनिज झारखंड में चल रहे हैं। सभी सार्वजनिक उपक्रमों में जरूरत से ज्यादा हजारों एकड़ जमीन ली गयी। लेकिन किसानों को न तो उचित मुआवजा मिला और ना ही नौकरी। सैकड़ों गांव झारखंड में समाप्त हो गए। हजारों आदिवासी, दलित, जंगल झाड़ में रहने वाले लोग समाप्त हो गए। आज उनकी अता पता नहीं है। जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार बड़े बड़े घरानों के खान खनिज के आवंटन कर रही है। राज्य में 33 कोल ब्लॉक खुलने जा रहे हैं उससे 3.30 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हो जाएंगे। लेकिन सरकार के पास कोई नीति नहीं है। राज्य के सभी जिलों में छोटे-छोटे समितियां बनाकर अपने अपने तरीके से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य विस्थापित संघर्ष मोर्चा बनाकर छोटी-छोटी लड़ाईयां लड़ने वाले सभी किसानों को एकजुट कर राज्य के स्तर पर बड़ी लड़ाई लड़ेगी और सरकार को विस्थापन आयोग, विस्थापन नीति बनाने एवं भूमि अधिग्रहण कानून 2000 लागू कराने के लिए मजबूर करेगी। भाकपा नेता मेहता ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि समय रहते किसानों के साथ न्याय नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में झारखंड के किसान सड़कों पर जोरदार आंदोलन

चतरा जिले के सिंहपुर कठौतिया रेल लाइन में हजारों एकड़ जमीन गैरमजरुआ जबरन लूटी जा रही है। तो भारतमाला एक्सप्रेस वे में भी किसानों की जमीन को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र हों या प्राइवेट सभी पुलिसिया डंडे के बल पर किसानों की जमीन लूट रहे हैं। जितने कोल ब्लॉक झारखंड में खुलेंगे

महेंद्र पाठक

आने वाले दिन में एक करोड़ लोग विस्थापित होंगे, राज्य में पहले ही 6500000 लोगों की जमीन जा चुकी है। लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं और जितने कोल ब्लॉक खान खनिज खुलने जा रहे हैं उससे 3.30 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हो जाएंगे। लेकिन सरकार के पास कोई नीति नहीं है। राज्य के सभी जिलों में छोटे-छोटे समितियां बनाकर अपने अपने तरीके से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य विस्थापित संघर्ष मोर्चा बनाकर छोटी-छोटी लड़ाईयां लड़ने वाले सभी किसानों को एकजुट कर राज्य के स्तर पर बड़ी लड़ाई लड़ेगी और सरकार को विरोध कर रहे किसानों पर लाठियां बरसाई गई। गोड्डा में अडानी प्रोजेक्ट के विरोध में चल रहे आंदोलन को कुचलने के लिए वहां के विधायक प्रदीप यादव को अदानी ने फंसा कर जेल भेजा। राज्य के खनिज संपदा को लूटने के लिए देश के कारपोरेट घराने बेताब हैं और राज्य में भाजपा की सरकार हो या झामुमो की सरकार हो मोटी थैली लेकर किसानों पर कहर बरपा रही है। राज्य में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू होता है भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की धारा 24 की भाग 2 के आधार पर हजारों एकड़ जमीन किसानों को वापस होगी। रांची के हटिया में कौड़ी के भाव में जमीन ली गयी, जमीन को सरकार करोड़ों करोड़ में बेच रही है। उसी तरह से हटिया बोकारो और कई जगहों पर जरूरत से अधिक जमीन का अधिग्रहण पूर्व में किया गया था। उसे किसानों को वापस किया जाना चाहिए। राज्य में पूर्व की भाजपा सरकार ने देश के बड़े बड़े पूँजीपतियों को झारखंड बुलाकर झारखंड की जमीन सौंप दी थी। राज्य के 2300000 हेक्टेयर गैरमजरुआ जमीन जो वर्षों से किसानों का पेट पालने का काम कर रही है। उस जमीन की रसीद बंद कर भूमि बैंक में डाल दिया गया। ताकि कारपोरेट घराने को मोटी रकम लेकर दिया जा सके। आज राज्य के चारों ओर किसान आंदोलन कर रहे हैं। जिसकी अगुवाई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है। आने वाले दिनों में यह लड़ाई एक बड़े आंदोलन का रूप

झारखंड में लेगी। जल्द ही राज्य में जेल भरो आंदोलन, आर्थिक नाकेबंदी, रांची में किसानों का महाकुंभ लगेगा। सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, किसानों से जो टकराएगा आने वाले दिनों 2024 में किसान उन्हें सबक सिखाएंगे।

महिला आयोग की पूर्व सदस्य वासवी किड़ो ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के गठन के बाद कोयले की परियोजना से लेकर राज्य के चारों ओर जमीन बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। राज्य के जंगलों में रहने वाले आदिवासी दलित शिकार हो रहे हैं। वर्तमान राज्य सरकार से लोगों की बहुत ही उम्मीद थी कि यह सरकार हमारी सरकार है। राज्य के किसानों, मजदूरों, विस्थापितों, नौजवानों, छात्रों, महिलाओं के साथ न्याय करेगी। लेकिन पूर्व की सरकार की तरह ही राज्य की हेमंत सरकार भी बर्ताव कर रही है। यह सरकार भी उसी तरह से कारपोरेट के साथ खड़ी है और किसानों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसीलिए राज्य में किसानों को बड़े आंदोलन की जरूरत है। सभा को भाकपा (मा), भाकपा (माले), झामुमो, राजद सहित कई संगठनों के नेताओं ने संबोधित किया और विस्थापितों के साथ खड़े होकर राज्य में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। झारखंड राज्य विस्थापित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम भाकपा के बैनर तले किया गया इसमें कई जन संगठनों के नेतृत्व के लोगों ने भाग लेकर किसानों के आंदोलन को समर्थन किया।

धरने में मुख्य रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, भाकपा राज्य सचिव महेंद्र पाठक, राजेंद्र प्रसाद यादव, बाबूलाल झा, अंबुज ठाकुर, अजय कुमार सिंह, इसहाक अंसारी, हसीब अंसारी, गणेश महतो, स्वयंबर पासवान, वासुदेव, अर्जुन कुमार दांगी, गयानाथ पांडे, बनवारी साहू, इम्तियाज खान, लखन महतो, बल्लू महतो, कमरुन्निसा, राजद के राजेश यादव, इकबाल अंसारी, सुफल महतो, सुरजीत सिन्हा, विध्याचल बेदिया, महादेव मांझी, मेमन यादव, जगन्नाथ पुरी, सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। आंधी, पानी, तूफान और बारिश के बावजूद राज्य के सैकड़ों लोगों ने झंडा बैनर तख्ती, गाजे-बाजे के साथ राजधानी में अडानी, अंबानी हटाओ, झारखंड बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, जैसे गगनभेदी नारे लगा रहे थे।



ગુજરાત પ્રલેસન્ કા 18વાં રાજ્ય સમ્મેલન સંપન્ન

સામાજિક સમરસતા હી ગુજરાત કી વર્ષો પુરાની વિરાસત

અહમદાબાદ, 25 જૂન 2023:

અહમદાબાદ મેં મહા ગુજરાત બેંક એમ્પ્લોયેજ એસોસિએશન કે ખચાખચ ભરે સભાક્ષણ મેં પ્રગતિશીલ લેખક સંઘ ગુજરાત કે 18વેં રાજ્ય સમ્મેલન કા ઉદ્ઘાટન દિલ્લી વિશ્વવિદ્યાલય કી અંગેજી સાહિત્ય કી પૂર્વ પ્રાધ્યાપક સ્વાતિ જોશી ને કિયા। સ્વયં એક સાહિત્ય પ્રેમી હોને કે સાથ હી સ્વાતિ જોશી ગુજરાતી સાહિત્ય કે પુરોધા ઔર જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર પ્રાપ્ત સાહિત્યકાર ઉમાશંકર જોશી કી પુત્રી ભી હૈની। અપને ઉદ્ઘાટન ભાષણ મેં સ્વાતિ જોશી ને દેશ દુનિયા કી સામાજિક રાજનીતિ ઔર સાહિત્યિક પરિસ્થિતિ પર વિદ્વત્પૂર્ણ ઢંગ સે પ્રકાશ ડાલા ઔર ન્યાયપૂર્ણ સંઘર્ષ કો જારી રખને કા આધ્વાહન કિયા।

રાજ્ય સમ્મેલન મેં પ્રગતિશીલ લેખક સંઘ કે રાષ્ટ્રીય સચિવ એવં સમ્મેલન કે પર્યવેક્ષક વિનીત તિવારી ને મુખ્ય વક્તા કે રૂપ મેં 'કલમ પર કસ્તી જંજીરે' વિષય પર મુખ્ય વક્તવ્ય દિયા। ઉન્હોને અનેક ઉદાહરણો દ્વારા વિષય વસ્તુ કો પ્રભાવી ઢંગ સે રખકર સમ્મેલન મેં ઉપરિશ્થ શ્રોતાઓં કો મંત્રમુદ્ધ કર દિયા।

સમ્મેલન કે પ્રારમ્ભ મેં પ્રગતિશીલ લેખક સંઘ કી ગુજરાત ઇકાઈ કે મહાસચિવ રામસાગર સિંહ પરિહાર ને ઉપરિશ્થ મહાનુભાવોં કી સ્વાગત કિયા। અપને સ્વાગત ભાષણ મેં ઉન્હોને કહા કી દેશ ઔર દુનિયા મેં ગુજરાત કો મોદી મૉડલ કા ગુજરાત કહા જાતા હૈ ઔર ઉસી કે આધાર પર ગુજરાત કો પરખને કા પ્રયાસ કિયા જાતા હૈ જો કી સચ નહીં હૈ। સહી મેં તો યહ કહી સુન્દરમ ઔર ઉમાશંકર જોશી

રામસાગર સિંહ

કા ગુજરાત હૈ જહીં 1932–33 મેં સુન્દરમ ને કોયા ભગત કી કડવી વાળી ઔર ગરીબોં કે ગીત લિખે જબ દેશ મેં પ્રગતિશીલ લેખક સંઘ કી સ્થાપના ભી નહીં હુઈ થી। ઇતના હી નહીં, ઉસકી પ્રસ્તાવના મેં ઉન્હોને સોવિયત સમાજવાદી ક્રાંતિ કા સ્વાગત કરતે હુએ ઉસકે અનુસરણ કરને કા આવાહન કિયા। ઉમાશંકર જોશી કા હૃદય વિશાળ થા। વે કહતે થે 'આઈ એમ ઇંડિયન પોએટ રિટન ઇન ગુજરાતી।'

ઇસલિએ મોદી કે પહલે ભી ગુજરાત થા ઔર મોદી કે બાદ ભી ગુજરાત રહેગા। ગુજરાત મેં સામાજિક સમરસતા વર્ષો સે રહી હૈ ઔર યહી કારણ હૈ કી જબ કોરોના કા કહર ચલ રહા થા ઔર કોરોના સે મરે હુએ લોગોં કે શવ ગંગા મેં તૈર રહે થે તબ સબરે પહલે ગુજરાત કી કવિયત્રી ને હી ઇસ ઘટના કો વિષયવસ્તુ બનાકર કવિતા લિખી થી।

સમ્મેલન કે પ્રથમ સત્ર મેં ગુજરાતી ઔર ઉર્દૂ સાહિત્ય પર ચર્ચા કી ગયી।

ગુજરાતી સાહિત્ય મેં અપની કમ ઉમ્ર મેં હી અત્યંત મહત્વપૂર્ણ રચનાએં પ્રદાન કરને વાલે સાહિત્યકાર ચુનીલાલ મડિયા કે ત્રિઅંકી નાટક 'રામલો રોંબિનહુડ' કી વ્યાખ્યા પ્રસ્તુત કરતે હુએ પ્રગતિશીલ લેખક સંઘ, ગુજરાત કે અધ્યક્ષમંડલ કે સદસ્ય ઔર જાને-માને સાહિત્યકાર ઔર કર્મશીલ મનીષી જાની ને નાટક કી વર્તમાન સમય કે પરિપ્રેક્ષ્ય વ્યાખ્યા કર ઔર ભી સાર્થક બના દિયા। યહ નાટક 1960 કે પહલે સૌરાષ્ટ્ર રાજ્ય કી હાલત પર લિખા ગયા થા લેકિન



મનીષી જાની કે પ્રસ્તુતીકરણ ને ઐસા ભાવ દૃશ્ય ઉત્પન્ન કર દિયા જैસે નાટક આજ કે સંદર્ભ મેં હી લિખા ગયા હૈ।

ઇસી સત્ર મેં મશહૂર શાયર રહમત અમરોહવી સાહબ કો ભી યાદ કિયા ગયા જિન્હોને ગુજરાત મેં તરક્કી પસંદ તહરીક કો મજબૂતી દી। અમરોહવી જી પર વલી ખાન ને આલેખ પ્રસ્તુત કિયા જિસમે ઉનું સાહિત્ય પર કરીને સે પ્રકાશ ડાલા ગયા।

'હર જોર-જુલ્મ કી ટકકર મેં હડ્ટાલ હમારા નારા હૈ' ગીત કો લિખને ઔર જીને વાલે પ્રગતિશીલ ગીતકાર ઔર કમ્યુનિસ્ટ આન્ડોલન ઔર ઇસ્ટ મેં કાર્ય કરને વાલે શંકર શૈલેન્ડ્ર કી જન્મ શતાબ્દી વર્ષ કે સંદર્ભ મેં પ્રગતિશીલ લેખક સંઘ, ગુજરાત રાજ્ય અધિવેશન કે દ્વિતીય સત્ર મેં, ઉન્હેં યાદ કિયા ગયા। જન કવિયત્રી સરૂપ ધ્રુવ કી અધ્યક્ષતા મેં જનકવિ શૈલેન્ડ્ર કી રચનાઓં કા પઠન-પાઠન એવં વિવેચના કી ગયી। ઇસ પરિચર્ચા મેં પ્રભા મજમૂદાર, સાહિલ પરમાર,



કરતાર સિંહ સિકરવાર એવં ઈશ્વર સિંહ ચૌહાન ને અપને વિચાર વ્યક્ત કિએ।

સમ્મેલન મેં આને વાલે તીન વર્ષો કે લિએ પદાધિકારી ચુને ગએ। અધ્યક્ષમંડલ મેં મનીષી જાની, ડૉ. અતુલ પાઠક, સાહિલ પરમાર, દિલીપ સિંહ ચૌહાન, ડૉ. ઈશ્વર સિંહ ચૌહાન, કરતારસિંહ સિકરવાર, સુગીત પાઠક, દલપત ચૌહાન ઔર રામસાગર સિંહ પરિહાર પ્રતિનિધિ ચુને ગએ।

સમ્મેલન કે અંત મેં પ્રગતિશીલ લેખક સંઘ કે રાષ્ટ્રીય સચિવ વિનીત તિવારી કા સમાન કરતે હુએ ઉન્હેં પુસ્તકે એવં સ્મૃતિ ચિન્હ કે રૂપ કર્છ કે ચિત્ર કી બનાવટ કા થેલા મેંટ કિયા ગયા।

સમ્મેલન મેં સ્વાગત સંચાલન ઔર આભાર રામસાગર સિંહ પરિહાર ને કિયા।



ललित कलाओं के क्षेत्र में संगीत और नृत्य, वास्तुकला और चित्रकला को मुस्लिम जगत में अपार संरक्षण मिला। चूंकि इस्लाम में मूर्तिपूजा वर्जित है, इसलिए शिल्पकला स्वभावतः ही घाटे में रही, हालांकि दक्षिण के अधिकांश मंदिरों और उड़ीसा तथा चंदेल के शिल्पित मूर्तियों युक्त मंदिरों का निर्माण मुसलमानों के आगमन के बाद ही हुआ। यह भी अर्थपूर्ण है कि संगीत के सिद्धांतों पर अधिकांश ग्रंथ, केवल भारत के नाट्यशास्त्र जैसे ग्रंथों को छोड़कर, मुसलमान संगीतकारों द्वारा गायन कला में योग देने के बाद रखे गये।

सूफी संतों ने सहज ही भारतीय संगीत को अपना लिया। वे बगदाद और फारस से आये थे। सुल्तान इल्तुमिश के दरबार में जिस पहले संगीतकार को गाने की अनुमति मिली थी, वह था हमीदुद्दीन—सुफियों का एक नेता, दार्शनिक और दिल्ली का काजी। संस्कृत में संगीत का महान ग्रंथ संगीतरत्नाकर 1238 में, इल्तुमिश के पुत्र सुल्तान फीरोजशाह के शासनकाल के दौरान, रचा गया। इसमें तत्कालीन कृति के लिए जाने तक उस विदेशी संगीत की सभी भाव-भंगिमाएं राज दरबारों में स्वीकृत हो चुकी थीं।

सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जो अन्यथा असामाजिक और क्रूर था, संगीत के प्रति गहराई से समर्पित था और उसने कला को प्रभुत संरक्षण दिया। भारतीय, फारसी और अरबी संगीत पद्धतियों को निकट लाया गया और उसके दरबार में हिंदू तथा मुसलमान, दोनों ही धर्मों की दूर्लभ प्रतिभाओं ने आश्रय लिया। चंगी, फतुहा, नसीर खां, बहरोज, अमीर खुसरो—ये सब अपने—अपने क्षेत्रों के उस्ताद थे।

अमीर खुसरो, जो खड़ी बोली की कविता का जन्मदाता था जिसका हस्ताक्षरित दीवान औरियंटल इंस्टीट्यूट, ताशकंद, में सुरक्षित है, अपने जमाने के महत्म गायकों में से था। उसने कवाली और तराना प्रारंभ कराये और जिलुफ, सपरदा, साजगीरी जैसे अनेक रागों का निर्माण किया। उस जमाने का एक सबसे प्रख्यात गायक नायक गोपाल था, जिसे अलाउद्दीन दक्षिण से लाया था। कहा जाता है कि वह दूसरों की उस्तादी के सामने झुक गया था। तबला और सितार (सेह तार, तीर तार) के अन्वेषण का श्रेय इन दोनों को ही दिया जाता है।

हिंदू और मुस्लिम पद्धतियों के संयोजन से संगीत में एक नये जीवन का आविर्भाव हुआ और अरबी तथा फारसी राग—जिलुफ, नौरोज, जांगुला, ईराक, यमन, हुसैनी, जिला दरबारी, हेज्जाज, खमाज—जनता और

भारतीय संस्कृति में इस्लाम का योगदान

भगवती शरण उपाध्याय

राजघरानों में अत्यंत लोकप्रिय हो गये। ध्रुपद मरणोन्मुख था, मगर दरबारों के संरक्षण में वह फिर जीवित हो उठा और कुछ शताब्दियों बाद तानसेन ने उसे अपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। ग्वालियर के राजा मानसिंह और जौनपुर के सुल्तान हुसैन शरकी, दोनों ही संगीत के अप्रतिम प्रेमी थे। राजा मानसिंह ध्रुपद के उस्ताद थे और सुल्तान हुसैन ने प्रसिद्ध राग हुसैनी, कान्हड़ा और तोड़ी अविष्कार किया। उसके दरबार में हिंदू और मुस्लिम, दोनों प्रख्यात संगीत के आवार्य थे—नायकबख्श, बैजू (बावरा), पांडवी, लोहुंग, जुर्जू, ढोड़ी और डालू।

अकबर के नवरत्नों में तानसेन सबसे बढ़ कर था। अबुल फजल ने 38 सर्वश्रेष्ठ दरबारी गायक गिनाये हैं, जो हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के मानने वाले थे। उनमें मांडू के सुलतान बाज बहादुर की संगीत मंडली भी आ मिली थी। सम्राट द्वारा संस्थापित धर्म दीन—ए-इलाही इतिहास से लुप्त हो गया, मगर जिस संगीत को उसने संरक्षण दिया था, और जिसका पोषण दोनों समुदायों ने किया था, दिन दून रात चौगुना वह बढ़ता रहा।

जहांगीर ने संगीत में अपने पिता की परंपरा जीवित रखी और उसके संरक्षण में चतर खां, पार्विजाद, जहांगीरदाद, खुर्मदाद, मक्कू, हमजान और विलास खां (तानसेन के पुत्र) ने तानसेन की आवाज को मरने नहीं दिया।

शाहजहां ने पंडितराज जगन्नाथ और दिरंग खां को चांदी से तौला। लालखां उस समय के संगीत में निष्णात था और उसे सम्राट ने गुण—समुद्र की उपाधि से विभूति किया।

अंग्रेजों के प्रवेश ने दरबारी जीवन को खतरनाक बना दिया। फिर भी मोहम्मद शाह रंगीला ने, नाविरशाह के आक्रमण के बावजूद, अदारंग, सदारंगा और शोरी आदि के जरिये संगीत की परंपरा को सुरक्षित रखा। शायद ख्याल कर अन्वेषण खुद सदारंग ने किया था, हालांकि उसे हुसैन शाह शरकी से भी जोड़ा जाता है। शोरी ने पंजाबी टप्पा को दरबारी राग में परिणत किया। इसके अलावा रेख्ता, कौल, तराना, तख्ता, गजल, कलबना, मर्सिया और सोज के भी गायक थे। अवध और रामपुर के नवाबों ने अपने संरक्षण के द्वारा समन्वित भारतीय संगीत को परिपूर्ण बनाया। वजीर खां बीनकार, प्यारेशाह ध्रुपदिया, मुस्तफा खां खयाली, फिदा हुसैन सरोदिया, मुहम्मद अली खां रुबाइया, इन सभी को मुस्लिम दरबार का संरक्षण प्राप्त था और इनके

मुसलमान और हिंदू दोनों ही समुदायों के प्रतिक्रियावादियों की असहिष्णुता और अंध पवित्रतावाद ने नृत्य को दरबारियों की शरण में जाने को मजबूर किया, फिर भी दोनों संप्रदायों के कई घराने हैं जो उसे अपने पसीने से पाल—पोस रहे हैं। संगीत के क्षेत्र में तो संप्रदायों के बीच विभेद को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया गया।

भारतीय वास्तु शिल्प में नवागंतुकों द्वारा दिये गये नये प्रतिमानों और शैलियों के कारण परिपूर्ण परिवर्तन आया। प्राचीन प्रतिमान और शैलियां छोड़ दी गयीं और काम्य विदेशी आकारों के स्पर्श ने भवनों में रूपांतर किया। और यह बात केवल वर्षों के लिए सही नहीं जहां मुसलमानों का वास था, बल्कि राजस्थान, मधुरा, वृद्धावन, काशी, मथुरा और काठमांडू जैसे स्थानों तक

में यह परिलक्षित होता है।

मुसलमानों ने अरब, फारस, फरगना से अपने नमूने लिये थे, मगर जिन हिंदू वास्तु शिल्पियों ने उन्हें बनाया, उन्हें स्थानीय बना दिया और मस्जिदों, मकबरों और महलों का रूप स्थानीय हो गया। गुबंद और कंगूर, मेहराबें और मीनारें दिल्ली और आगरा, अजमेर और सासाराम, जौनपुर और गौड़, मालवा और गुजरात के भवनों को सुशोभित कर रही हैं, और आरंभिक चरणों में हिंदू तथा मुस्लिम कलावास्तु में विभेद कर पाना कठिन हो जाता है।

दोनों की शैलियां दूध—पानी की तरह मिल गयी हैं। निर्धारित करने वाला तत्व मात्र सौंदर्य शास्त्र, रूप का सौंदर्य, भावना की उदात्तता ही रह जाता है। मुसलमानों ने अपना नव—निर्वाचित गृह ऐसे बनाये जैसा कि पहले कहीं नहीं बनाये थे। मुस्लिम जगत में भारत से बाहर कहीं भी दिल्ली और आगरा से भव्यतर किले नहीं, कुतुब से बढ़ कर

मीनार नहीं, सीकरी के बुलंद दरवाजा से बढ़िया कोई द्वार नहीं, मोती और जामा मस्जिद से अधिक सुंदर कोई मस्जिद नहीं, और ताज के मकबरे से बढ़कर कमनीय सुंदर और आकर्षक कोई मकबरा नहीं। दुनिया में कोई देश नहीं जो भारत में सर्वधृत मुस्लिम स्मारकों की होड़ संख्या, विविधता या सौंदर्य की दृष्टि से कर सके। प्राचीन जनों ने एक नया जीवन पाया और इसे नयी शक्तियों ने जो ताजगी दी थी उसे अपनाया। आम प्रयलों के द्वारा एक समान विरासत रखी गयी। राजपूताना के राजाओं ने मुगलों का अनुसरण किया और अपने महल, यहां तक कि अपनी छतरियां मुस्लिम शैली में बनवायीं। वे मुगल वेशभूषा पहनते और अपने दरबारों में भी मुगल शिष्टाचार को बरतते थे।

चित्रकला में फारसी शैली से बिल्कुल भिन्न एक नयी शैली—मुगल काल—ने भारत को गौरव प्रदान किया। यद्यपि यह शैली फारस से आयी थी, मुस्लिम तथा हिंदू कंकी से पल—पूस कर यह पूर्णतः भारतीय हो गयी। भारत अभी भी गुजरात, दक्षिण और राजस्थान में चित्रकला की अपनी शैलियां विकसित कर रहा था जहां रागों की भाव—भंगिमाएं भी रेखा और रंग द्वारा चित्रित करने का प्रयत्न हो रहा था। लेकिन नये प्रभावों ने हिंदू कलाकारों को नयी शक्ति दी और उनके सामने सृजन के नये आयाम, नयी गहराई, नयी लय और नया छंद खोल दिया। चीनी पृष्ठभूमि में उठी चंगताई शैली ईरान में चरमोत्कर्ष पर थी और फारसी कलम का संयोग पाकर, मुगल कलम

ने एक नया लालित्य ग्रहण किया। इस उल्लेखनीय समन्वय ने नयी जमीनें तैयार की और जम्मू और कांगड़ा की पहाड़ियों में, लखनऊ और पटना और दक्षिण में चित्रकला पुष्टि होने लगी।

मुगल दरबारों ने हिंदू और मुसलमान कलाकारों को साथ—साथ रखा, और अबुल फजल ने फारूख कलूमक, अब्दुस्समाद सिराजी, मीर सैयद अली और मिस्की के साथ—साथ दसवंत, बसावन केसोलाल, मुकुंद, माधो, जगन्नाथ, महेश, मकरण, तारा, सांवला, हरिबंश और राम जैसे चित्रकलारों का उल्लेख किया है। पटना में खुदाबक्श लाइब्रेरी में प्रदर्शित भव्य तैमुरनामा की पांडुलिपि ने हिंदू कलाकारों की सूची में अनेक नाम जोड़े गये हैं—तुलसी, सुरजन, सूरदास, ईसर, शंकर, रामजस, बनवारी, नंद, नन्हा, जगजीवन, धरमदास, नारायण, चतरमन, सूरज, देवाजीव, सरन, गंगासिंह, पारस, घना, भीम तथा अन्य, जिन्हें दरबार ने काम सौंपा था, जिसके लिए वे गवालियर, कश्मीर और गुजरात से आये थे।

शाहजहां के शासन काल में मुगल कलम ने अपने चमत्कार दिखाये, जब मुहम्मद नादिर, समरकंदी, पोर्टेट कला के जादूगर मीर हासिम और मुहम्मद फकरिल्लाह खां ने कल्याणदास, चतरमन, अनूप, चतुर, राम और मनोहर के साथ एक टीम में काम किया।

एआईएसएफ तेलंगाना राज्य का तीन दिवसीय शिक्षण कार्यक्रम



राम नरसिंहा राव

साम्यवादी विचारधारा पर एआईएसएफ तेलंगाना ने एआईएसएफ सदस्यों के लिए तीन दिवसीय छात्र शिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम से पूर्व एआईएसएफ राज्य सचिव पुष्टा लक्ष्मण के नेतृत्व में दो किमी लंबा पैदल मार्च निकाला गया। इस मार्च में एआईएसएफ तेलंगाना राज्य के सदस्यों, ब्लॉक, जिला, राज्य पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। राज्य के पूर्व महासचिव एन. बालामल्लेश ने एआईएसएफ झंडातोलन किया।

इस कार्यक्रम के बाद छात्र शिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन पर भाकपा तेलंगाना राज्य सचिव कुनामेनी संबांशिव राव ने शिक्षा के संबंध में वैज्ञानिक वृष्टिकोण की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि छात्र समुदाय जहां शिक्षा व्यवस्था पर पुरातन पंथी हमलों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और समाजवादी समाज की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं छात्रों को व्यवस्था से लेकर रोजमर्ग के असमान संबंधों पर सवाल उठाते हुए समाज में मौजूद अनेकों बुराइयों से लड़ना होगा।

उन्होंने कहा कि एआईएसएफ देश का अग्रणी छात्र संगठन है। एआईएसएफ ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई में छात्रों और युवाओं को संगठित किया था। एआईएसएफ छात्र समुदाय में सवाल करने की प्रकृति को विकसित करने का हिमायती रहा है। उन्होंने देश के वर्तमान राजनीतिक परिवृश्यों में अधोषित आपातकालीन स्थिति का हवाला देते हुए बताया कि कई कवियों, लेखकों, पत्रकारों, शिक्षकों एवं बुद्धिजीवियों पर गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) एकत्र (यूएपीए) लगाकर उन्हें जेल में उत्पीड़ित किया जा रहा है। उन्होंने छात्रों से समाज के ध्रुवीकरण के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया।

उद्घाटन अवसर पर मूर्ती आर्टिस्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मादाला रवि ने छात्रों से उम्मीद की अपेक्षा करते हुए कहा कि आज के छात्र कल के नागरिक और भविष्य निर्माता हैं। आपको कई चीजें सीखनी हैं। उन्होंने छात्रों से लगन से पढ़ने और सवाल पूछने की मानसिकता विकसित करने की अपील की।



पी.पी.एच. पब्लिकेशन

पुस्तक

1. भारतीय दर्शन में क्या जीवंत है और क्या मृत
2. बाल जीवनी माला
3. बाल जीवनी माला
4. बाल जीवनी माला
5. बाल जीवनी माला
6. बाल जीवनी माला
7. बाल जीवनी माला
8. बाल जीवनी माला
9. बाल जीवनी माला
10. बाल जीवनी माला
11. फैज अहमद फैज-शख्स और शायर
12. फांसी के तख्ते से
13. कितने दोबाटिक सिंह भारत विभाजन की

दस कहानियां

14. मार्क्सवाद क्या है?

15. फैज अहमद फैज: प्रतिनिधि कविताएं

16. दर्शन की दरिद्रता

17. हिन्दू पहचान की खोज

18. प्राचीन भारत में भौतिकवाद

19. 'जब मैंने जाति छिपायी थी' तथा अन्य कहानियां

20. बाल-हृदय की गहराइयां

- माँ-बाप और शिक्षकों से अंतरंग बातचीत

21. चीन की पुरस्कृत कहानियां भाग-1, 2

22. बच्चों सुनो कहानी

23. जहां चाह वहां राह-उज्ज्बेक लोक कथाएं

24. हीरेमोती-सोवियत भूमि की जातियों की लीक कथाएं

25. दास्तान-ए-नसस्तीनी

26. लेनिन-क्रुप्स्काया (संस्मरण)

27. साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की चरम अवस्था

28. बिसात-ए-रक्स

29. भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण

30. राहुल निबंधावली (साहित्य)

31. मैं नास्तिक क्यों हूं

32. विवेकानंद सामाजिक-राजनीतिक विचार

33. रामराज्य और मार्क्सवाद

34. कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र

35. भगत सिंह की राह पर

36. माटी का लाल-कृति पुरुष कामरेड दुर्जन भाई

37. क्या करें

38. मैक इन इंडिया -आंखों में धूल

39. भारतीय इतिहास में जाति और मुद्रा

40. वर्ग जाति आरक्षण और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष

लेखक

- देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय 500.00

- कॉर्परनिक्स 12.00

- निराला 12.00

- रामानुज 12.00

- मेंडलिफ 50.00

- प्रेमचंद 50.00

- सी.पी. रमन 50.00

- आइजक न्यूटन 50.00

- लुईपाश्चर 50.00

- जगदीश चन्द्र बसु 50.00

- शकील सिद्दीकी 80.00

- जूलियस फ्यूचिक 100.00

- भूमिका: भीष्म साहनी 60.00

- एमिल बर्न्स 40.00

- संप श्री अली जावेद 60.00

- कार्ल मार्क्स 125.00

- डी.एन. झा 100.00

- देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय 200.00

- बाबुराव बागुल 200.00

- वसीली सुखोम्लीन्स्की 350.00

- 185.00

- लेव तोलस्तोय 175.00

- 360.00

- 300.00

- लियोनिद सोलोवयेव 370.00

- क्रुप्स्काया 485.00

- लेनिन 65.00

- मङ्खदूम 100.00

- भगवत शरण उपाध्याय 100.00

- राहुल सांकृत्यायन 90.00

- भगत सिंह 75.00

- विनोय के. राय 75.00

- राहुल सांकृत्यायन 60.00

- मार्क्स एंगेल्स 50.00

- ए.बी. बर्धन 15.00

- डा. रामचन्द्र 110.00

- लेनिन 80.00

- सी. मुरलीधर, एम. सत्यानन्द 30.00

- इरफान हबीब 40.00

- 6.00

दिल्ली के शोरूम

- जी-18, आउटर सर्कल, कनाट प्लेस

- नई दिल्ली-110001, फोन: 23324064

- पीपीएच बुकशॉप, जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी के पास,

- नई दिल्ली-110067, फोन: 65447645

- पीपीएच शॉप, अजय भवन

- 15, कामरेड इन्ड्रजीत गुप्त मार्ग, नई दिल्ली-2

नोट: आप भेज सकते हैं:

चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रानिक मनिआर्डर "पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड" के पक्ष में

बैंक विवरण:

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट: 32074674284, आई.एफ.सी. कोड: SBIN0009371

भारतीय संस्कृति में इस्लाम का...

पेज 13 से जारी...

का दल करता था जिनमें से कुछ लोगों की विस्तृत सूची अबुल फजल ने दी है। आगरा के शाही पुस्तकालय में 24,000 पुस्तकों थीं जिनमें से लगभग सभी सचित्र थीं। इनमें से अधिकांश पुस्तकों विजेताओं के लोभ और कलाकृतियों के व्यापारियों की मुनाफाखोरी के कारण अब दुनिया के विभिन्न संग्रहालयों में पहुंच गयी हैं। कुछ विशिष्ट पुस्तकों आज पटना के खुदाबख्श पुस्तकालय में सुरक्षित हैं।

किताबत, हाशियागरी और जिल्दसाजी का भी उतना ही गौरवपूर्ण स्थान था जितना मुगल चित्रकला का। किताबत का विकास मुख्यतः चीन में हुआ जहां प्रत्येक अक्षर का अंकन एक नन्हे से चित्र या सूक्ष्म रेखाकंन के रूप में होता था। ईरान तथा अन्य मुस्लिम देशों में इसको सुधारने—संवारने के लिए उर्वर भूमि मिली। चूंकि मनुष्य का चित्रांकन मूर्तिं-पूजा के वर्जित होने के कारण मना था, चित्रकारों ने अपने कौशल को हस्तलिपि सुंदर बनाने में किया। यद्यपि ईरान में मनुष्य का चित्र न बनाने की हड तक कभी पाबंदी नहीं रही, फिर भी वहां किताबत का भी विकास किया गया। लेकिन मुगलों ने भारत में इस कला को सर्वांग संपन्न किया क्योंकि कहूर धार्मिक वर्जनाओं के दमन को वे काफी आगे तक ले गये। इसी प्रकार हाशियागरी को भी मुगल विशेषज्ञों ने इस बारीकी से विकसित किया कि वे दुनिया में अपने किस्म के श्रेष्ठ उदाहरण बन गये। पुरानी पाण्डुलिपियों को सुरक्षित रखने की वृष्टि से चमड़े की जिल्दसाजी की कला में इटली और फ्रांस-इटली में विशेषकर वेनिस नगर—ने कुशलता उपलब्ध की थी। वास्तव में चीन की ही तरह, उन्होंने भी एक मुश्किल मिसाल पेश की जिसकी नकल कर पाना कठिन था, मगर मुगल जिल्दसाजों ने इस कला में अपनी अनन्य प्रवीणता स्थापित कर दी। जिल्द, खुदे हुए अक्षरों और सारी साज-सज्जा में ऐसी कोई बात नहीं

बची जिसकी और आवश्यकता हो और इस प्रकार उन्होंने जिल्दसाजी की दुनिया में एक चमत्कार पैदा कर दिया। जो भी कुछ गौरवशाली था, वह सब मौलिक और अनुदित ग्रंथों के रूप में और सूक्ष्म चित्रों से साज कर जुटा लिया गया था। इन सचित्र पुस्तकों के एक पृष्ठ की भी दुनिया के कला—बाजार में भारी कीमत मिल सकती है। बड़ी से बड़ी कीमत पर उन पुस्तकों को हासिल किया गया था।

कुछ अपवादों को छोड़ समस्त मुगल चित्रकारी कागज पर की गयी थी। चीनी चित्रकारी की तरह उसको सिल्क पर कभी नहीं किया गया। मुगलों के साथ भारत-ईरानी कलाकार टीम की तरह काम करते थे। चित्रफलक को पहले वे चौकोर रेखाओं से घेर देते। पुस्तक के छोटे चित्र अंकित करने से पहले वे लाल या काली खड़िया से रेखाचित्र बनाते और उसके बाद उसमें आवश्यक रंग भरते थे। मूल्यवान पुस्तकों को सचित्र बनाने के लिए वे जटिल प्रणाली का उपयोग करते थे। वे पृष्ठ खाली छोड़ देते, स्वतंत्र रूप से चित्र तैयार करते और उसको खाली स्थान में चिपका देते थे। पहले अरबी गोंद पानी में मिला कर एक घोल तैयार किया जाता था। इसको पृष्ठ पर लगा दिया जाता था और इस तरह जो चिकनी और चमकदार सतह तैयार होती थी, उस पर रेखाचित्र बनाया जाता था। तैल-चित्र प्रणाली के अनुसार रंगों की कई तरहें जमायी जाती थीं। कभी—कभी मोतियों, हीरों और सोने का प्रभाव पैदा करने के लिए इनके कण चिपका दिये जाते थे और इस प्रकार चित्रित व्यक्ति के आभूषणों के असली होने का वांछित भ्रम पैदा किया जाता था। यह काम सुईकारी से अधिक सूक्ष्म था और मुस्लिम विशेषज्ञों के साथ हिंदू चित्रकार टीम के रूप में काम करते हुए गिलहरी के बालों से बने ब्रशों से वह कला संपन्न करते थे। जहां काम बड़ा बारीक होता, वहां कभी—कभी एक बाल के ब्रश का उपयोग किया जाता था। जब एक चित्र पर कई चित्रकार काम करते

तब प्रत्येक कलाकार की विशिष्ट प्रतिभा को विशेष स्थल चित्रित करने के लिए उपयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए, एक चित्रकाल घोल तैयार कर पृष्ठभूमि बनाने का काम करता, दूसरा रेखांकन तैयार करने में पटु था और रेखाचित्र तैयार करता था और तीसरा उसको आवश्यक रंगों से भर देता था। दक्षिण केसिंगटन संग्रहालय में सुरक्षित अक्षरनामा में अधम खान का फांसी के चित्र में रेखांकन मिस्किन ने किया था, लेकिन रंग शंकर ने भरे थे। एक और चित्र मानवाकृति में रेखाचित्र मिस्किन ने तैयार किया था, रंग भरने का काम सरवन ने किया, तीसरे चित्रकार ने उभार तैयार किये और चित्र बनाने और संपन्न करने का काम माधो ने किया था। रंगों के उपयोग और उनमें नजाकत पैदा करने में हिंदू और मुसलमान चित्रकारों ने अपने ईरानी उस्तादों को मात कर दिया था। प्राकृतिक चित्रण के क्षेत्र में ईरानियों में उनके कोई सानी नहीं था।

जैसा ऊपर बताया गया है, पुस्तकों में बनाये जाने वाले छोटे चित्रों का निर्माण मुगल काल में बढ़े ऐपाने पर किया गया। रामायण और महाभारत दोनों का ही फारसी में अनुवाद किया गया और आकर्षक लघु चित्रों से उनको सचित्र बनाया गया। महाभारत के अनुवाद का नाम है रजूनामा। इसी सचित्र शैली में दास्तानेहमजा तैयार किया गया। रसिकप्रिया की चमत्कारपूर्ण चित्रों से सज्जित पाण्डुलिपि भी सुरक्षित है। सचित्र प्रतिलिपि बनाने की कला का वह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसी प्रकार एक और सचित्र पुस्तक तैमूरनामा की प्रति खुदाबख्श पुस्तकालय की अमूल्य निधि है।

सचित्र पुस्तकों के अतिरिक्त पोट्रेंट चित्रांकन भी हिंदू और मुसलमान चित्रकारों की समन्वित साधना की उपलब्धि है। मुगल समारों और राजकुमारों के कुछ पोट्रेंट अप्रतिम और अनन्य हैं। इनमें से कुछ लंदन के इंडिया ऑफिस पुस्तकालय में प्रदर्शित हैं। वे दाराशिकोह के अल्बम के अंग थे जिसको उसने अपने हस्ताक्षर सहित सप्रेम नादिरा बेगम को भेंट किया था।

सत्ता से भाजपा की विदाई तय कर दी है। पटना पहुंचने पर भाकपा महासचिव का किया गया जोरदार स्वागत। 23 जून को राजधानी पटना में विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर होने वाली बैठक में शामिल होने पहुंचे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी. राजा का गुरुवार को पटना हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत किया गया। पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय, बिहार सरकार के

पशु-पक्षियों के चित्र मुगल उस्तादों की महत्म कला—उपलब्धियों में से हैं। इस क्षेत्र में मंसूर का कोई सानी नहीं था। जहांगीर के संरक्षण में बनाये गये मुर्गों के चित्र, जो अब कलकत्ता आर्ट गैलरी में सुरक्षित हैं, की बाबारी चीनी उस्ताद भी नहीं कर सकते जिन्हें पशु-पक्षियों के सर्वोत्तम चित्र बनाने का श्रेय दिया जाता है।

भारतीय पोशाक में भारी तबदीली आयी। शक और कुषाण लोगों ने यहां ईरानी पद्धति चलानी चाही और विफल रहे। लेकिन मुगल दरबारों ने एक नया नमूना पेश किया और मुगल पोशाक पहने मानसिंह और महावतखां में फक्र कर सकना कठिन हो गया। यह अत्यंत हर्षजनक है कि मुगल सल्तनत के कट्टर दुश्मन राणा प्रताप और शिवाजी तक भव्य मुगल पोशाक पहनते थे। मुगलों ने जो कुछ शुरू किया था उसे अवध के नवाबों ने सर्वांग संपन्न बनाया और भारतीय सरकार ने अचकन तथा पाजामा को अपनी राष्ट्रीय पोशाक मान लिया। तुक, पठान और मुगलों द्वारा प्रचलित जुराब और मोजा, जोरा और जामा, कुर्ता और कमीज, ऐच, चोगा और मिर्जई दिल्ली और लखनऊ के दरबारों में भी उसी प्रकार पहनी जाने लगीं, जैसे बंगाल के पंडितों द्वारा।

इस सिलसिले में, मुसलमानों ने हिंदू वधू को जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण आभूषण दिया है, उसका उल्लेख उपयोगी होगा। नथ आज हिंदू विवाह का अनिवार्य प्रतीक बन गयी है। नथ को किसी भी हिंदू देवी की मूर्ति ने धारण नहीं किया यहीं नहीं, संस्कृत भाषा के अपार शब्द भंडार के अंग बन गये। दक्षिण की चारों भाषाएं भी इनसे अछूती नहीं रहीं, मुसलमानों की बोली और लिखित भाषा का प्रभाव इतना व्यापक था। सबसे अधिक प्रभावित हुई हिंदी, जो शब्दावली और शैली में स्वयं तो प्रभावित हुई ही, उसके फलस्वरूप मानों उसने एक रूप में जन्म लिया जिसे उर्दू कहते हैं और जिसने नयी विरासत को सर्वांग से इस्तेमाल किया और फारसी लिपि में दायें से बारीं और लिखी जाने लगी। एक नये साहित्य का जन्म हुआ, उर्दू साहित्य का, जो इसी भूमि की उपज था, यहां ही बोला, लिखा और विकसित किया गया।

दलों की एकजुटता और एकता जरूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आमंत्रण पर विपक्षी दलों की एकजुटता से साफ है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व गठबंधन की करारी हार होने वाली है। डी. राजा ने बताया कि मोदी सरकार जिस तरह से संवेदनशील संस्थाओं को नष्ट कर रही है, उससे संविधान खतरे में है। मौजूदा केंद्र सरकार सिर्फ पूँजीपतियों के लिए काम कर रही है। बीते नौ साल में श्रमिकों, किसानों, बेरोजगारों और नौजवानों के लिए मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया।

भाजपा को 2024 आम चुनावों में ...

पेज 1 से जारी...

एक प्रक्रिया है, जो आगे बढ़ने जा रही है।

राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा कि अब मैं पूरी तरह फिट हूँ। अब नरेन्द्र मोदी और भाजपा को फिट कर देना है। उन्होंने महंगाई, दो हजार रुपये के नोट बंद करने और कर्नाटक चुनाव चुनाव में भाजपा की हार पर भी तंज

सत्ता से भाजपा की विदाई तय कर दी है।

पटना पहुंचने पर भाकपा महासचिव का किया गया जोरदार स्वागत।

23 जून को राजधानी पटना में विपक्षी दलो

मणिपुर की जनता का जातीय बंटवारा

शासकों की बेपरवाही से लहूलुहान मणिपुर

नई दिल्ली में 25 जून 2023 को "मणिपुर में शांति के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन" की सभा को संबोधित करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी. राजा ने कहा कि, "मणिपुर का मौजूदा उत्पात 'डबल इंजन' वाली भाजपा सरकार द्वारा चलाई गई लोगों को बांटने की राजनीति का प्रत्यक्ष नतीजा है। इस ज्वलंत समस्या के राजनीतिक समाधान के लिए राज्य में समाज के सभी समुदायों के विचारों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है।" उन्होंने कहा कि राज्य में अमन और स्थिति सामान्य होनी चाहिए। मणिपुर के सभी समुदायों से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शांति बनाए रखने की अपील करती है।

इस धरने को मणिपुर पर मिलती-जुलती सोच रखने वाली राजनीतिक पार्टियाँ और जनसंगठनों ने आयोजित किया था वे पार्टियाँ और संगठन हैं भाकपा, भाकपा (मा) काँग्रेस, एटक, एनएफआईडब्ल्यू, एआईएफबी, आरएसपी, जेडीयू, एनसीपी, एसएस (यूबीटी) और आप। मणिपुर से पार्टी के राज्य नेतृत्व दल के अलावा, इस सम्मेलन सभा में राष्ट्रीय सचिवमण्डल डॉ. के नारायणा, पल्लव सेनगुप्ता, दिल्ली भाकपा राज्य सचिव दिनेश वार्ष्ण्य भी सम्मिलित थे। मंच पर उपस्थित अन्य दलों के नेता जयराम रमेश, मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री इबोबी सिंह, भाकपा (मा) पोलित ब्युरो सदस्य नीलोत्पल बसु, एआईएफबी के महासचिव जी देवराजन, आरएसपी के आर एस डागर, भाकपा मणिपुर राज्य सचिव एल थोरेन। भाकपा मणिपुर राज्य सहायक सचिव जॉय कुमार ने कन्वेन्शन का संचालन किया।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मणिपुर राज्य परिषद और दिल्ली राज्य परिषद ने मणिपुर में पिछले पचास दिनों से जारी हिंसा के विरोध में और मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री की बेरहम चुप्पी के विरोध में जंतर मंतर पर भारी प्रदर्शन किया।

सम्मेलन की अध्यक्षता एल



सोतिन कुमार ने की। धरने को संबोधित करने वाले अन्य वक्ताओं में भाकपा नेता डॉ. के नारायणा, रामकृष्ण पांडा, राज्यसभा सदस्य पी संदोष कुमार, एल थॉइरेन, एन सिंहजीत, जॉय कुमार, एटक नेता शाहमुग्गौ सिंह, एनएफआईडब्ल्यू सचिव प्रेमिल, जिला परिषद सदस्य नूर, भाकपा (मा) मणिपुर राज्य सचिव के शांता, दिनेश वार्ष्ण्य, एआईवार्फाएफ

के अध्यक्ष सुखजिन्दर महेसरी, बीकैएमयू महासचिव गुलजार सिंह गोरिया, भाकपा (मा) के एन तौंबीचामु शामिल थे।

इन सभी वक्ताओं के भाषण में मणिपुर के वर्तमान संकट पर गहरी चिंता व्यक्त की गयी थी। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक संकट है इसलिए इसका समाधान भी राजनीतिक होना चाहिए। हिंसा पर

अविलंब रोक और शांति बहाली की मांग की गई। उन्होंने कहा कि मणिपुर में भाजपा सरकार की संकीर्ण राजनीति के कारण यह जातीय हिंसा शुरू हुई है और उन्होंने मांग उठाई कि केन्द्र सरकार तत्काल मणिपुर में सभी राजनीतिक पार्टियों की बैठक करे। सम्मेलन के दौरान उठाई गई कुछ तत्काल मांगें जैसे कि विस्थापित लोगों के लिए विशेष राहत पैकेज, नेशनल हाइवे नंबर दो पर से अवरोध हटाना, मणिपुर में मादक पदार्थों के आतंक को रोकना। मणिपुर और केंद्र में भाजपा नीत सरकार की मणिपुर में लोगों को विभाजित करने की कोशिश, जो कि पहले ही हिंसा की आग में जल रहा है, का एकमात्र उद्देश्य चुनावी लाभ है। इस चहुंमुखी हिंसा की पृष्ठभूमि में विभाजनकारी नीतियाँ हैं और इस हिंसा को खासतौर से केन्द्रीय गृहमंत्री और राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से चिरस्थायी रूप से नहीं नियंत्रित किया जा सकता है।

प्रत्येक दिन लोग मर रहे हैं। जो जीवित हैं उन्होंने अपने घर खो दिए हैं। उनके घर राख में बदल गए हैं और उनकी दुकानें लूटी और जला दी गई हैं।

यह एक आम दृश्य बन गया है। त्रासदी से घिरे लोगों की जिंदगी पर उधमी फल-फूल रहे हैं घरों को जलाते देखना और दुकानों को लूटते

देखना आम बात हो गई है। जातीय द्वन्द्व हिंसा के भयावह स्तर पर पहुँच गया है और यह दिखाता है कि मणिपुर की जनता का राज्य मशीनरी से विश्वास उठ गया है।

भाकपा की समझ है कि राजनीतिक और सामाजिक द्वन्द्व इस तबाही का कारण है और यह तबाही मात्र कानून और व्यवस्था का विषय नहीं है। पार्टी मांग करती है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय और स्वयं मणिपुर राज्य सरकार हिंसा की स्थिति को तत्काल रोकने के लिए समाज के सभी समूह के प्रतिनिधियों और राजनीतिक पार्टियों के साथ बातचीत करे।

इस संकट के राजनीतिक समाधान के लिए सभी समुदायों और राजनीतिक पार्टियों के विचारों को ध्यान में रखना चाहिए और मणिपुर में सामान्य स्थिति और शांति बहाल करनी चाहिए। भाकपा मणिपुर के सभी समुदाय के लोगों से सामान्य स्थिति और शांति बनाए रखने की अपील करती है।

धरने में भाकपा दिल्ली राज्य नेता केहर सिंह, राम राज, अजय मलिक, भाकपा दिल्ली राज्य समिति के समस्त सचिवमण्डल सदस्य आर पी अत्तरी, संजीव कुमार राणा, नीरज कुमार, बबन कुमार सिंह के अलावा भाकपा दिल्ली राज्य परिषद सदस्य हैंदर अली, मुस्लिम मोहम्मद और भाकपा दक्षिण दिल्ली जिला परिषद के सदस्य शामिल थे।

